साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 03 में...
परंपराएं
हुई ध्वस्त

पेज 12 में...
पैसा खुदा तो नहीं
फंस गए बिट्टू

वर्ष : 01 अंक : 20 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 07 टीम इंडिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़!

'मदन' कुक, भृत्य बाबू या 'छलिया'

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में 5 लोगों का नियुक्ति विवाद

कटघरे में है संविलियन, नियमितीकरण और पदोन्नति

केंद्रीय कार्मिक विभाग, मप्र.-छग. में कैडर अलग-अलग

तदर्थ से नियमित और फिर धड़ल्ले से मिलता रहा प्रमोशन

बिना अनुमति दुबई, थाईलैंड, नेपाल की 6 दफा विदेश यात्रा

डायरेक्टर हेल्थ में 25 में 12 साल बजट शाखा में पदस्थ रहा

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित की गई 5 सदस्यीय विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट में जिस मदन विश्वकर्मा की पदस्थापना से लेकर पदोन्नति तक को नियम विरुद्ध ठहराया जा चूका है। शासन के नियमों की अनदेखी करते हुए ऐसे 5 विभागीय लोगों पर समिति ने सख्त अभिमत स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2022 में भेज दिया गया है उन पर कार्रवाई की बजाये पुनः पदोन्नति से नवाजने की तैयारी है। DHS यानि की संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ में कार्यरत मदन कुमार विश्वकर्मा, कैलाश कुमार सेन, मरियम्मा मैथ्यू और केके.सोनी (सेवानिवृत)दो दशक से फर्जी तरीके से वेतन, पदोन्नति और पदस्थापना ही नियम विरुद्ध है। सबसे विवादित स्टाफ में मदन कुमार विश्वकर्मा का नाम चर्चित है। तदर्थ मानदेय नियुक्ति (अनियमित) से छत्तीसगढ़ आकर नियमित होने और फिर धड़ाधड़ पदोन्नति, फिर 12साल बजट शाखा में रहते हुए विदेश यात्रा करने वाले विवादित मदन विश्वकर्मा को जल्द विभाग सहायक अधीक्षक से प्रशासनिक अधिकारी (DHS में AO प्रमोशन)बनाने वाला है।

शहर सत्ता/रायपुर। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन में चौकाने वाला तथ्य सामने आया है। वर्ष 1994 में मदन विश्वकर्मा जिनकी अस्थाई नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन में हुई थी। इसके बाद नवबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से विभाजित होने के साथ ही विभाग के कई कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र भी बदल गया। राज्य विभाजित होने के बाद कर्मचारियों की जो सूची मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी की थी उस सूची में मदन विश्वकर्मा का नाम ही नही है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे और किन नियमों के तहत संचानालय स्वास्थ्य सेवाएं नवा रायपुर के बजट शाखा जैसे अहम महकमे में लंबी पारी खेल चुके कार्यरत सहायक ग्रेड एक में तैनात हैं?

इतना ही नही मदन विश्वकर्मा की पदोन्नति महज एक से तीन साल के भीतर भृत्य से लेकर सहायक ग्रेड तीन, सहायक ग्रेड दो और सहायक ग्रेड एक में नियम विरुद्ध पदोन्नत करने का मामला विभागीय जांच समिति नियम विरुद्ध ठहराया है। शहर सत्ता को प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है की मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आये उक्त लोग नियम विरुद्ध हैं। 19 दिसम्बर 1994 में मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में मदन विश्वकर्मा की अस्थाई नियुक्ति राज्य स्तरीय राजीव गाँधी मिशन सेल भोपाल के आयोडीन अल्पता विकार निवारण कार्यक्रम में भृत्य के पद पर हुई थी। इसके बाद नवम्बर 2000 में राज्य गठन होने बाद कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए चुतर्थ ग्रेड की जिन कर्मचारियों की सूची मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था उसमे कहीं पर भी मदन विश्वकर्मा का नाम ही नही है। और न ही उनका छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में संविलियन हुआ है।

बावजूद इसके वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने 29 मार्च 2001 का हवाला देकर 28 मई 2004 को आदेश जारी करते हुए चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी मदन विश्वकर्मा को छोड़ कन्छेदी लाल मेहरा और कैलाश कुमार सेन का नाम सूची में शामिल को सहायक ग्रेड तीन पर तदर्थ रूप से पदोन्नत करते हुए नियमित करने का आदेश जारी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 29 मार्च 2001 को कर्मचारी मदन विश्वकर्मा के नाम से पदोन्नत, और संविलियन करने संबधी कोई भी नोटशीट की फाईल नही चली है और एक साल में तदर्थ से पदोन्नत होने के साथ ही संविलियन भी कर दिया गया। जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीयों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।

संचालक स्तर के अधिकारी ही प्रमोशन कर सकते है। नियम के मुताबिक मदन विश्वकर्मा को संविलियन करने के पश्चात् नियमित किया जाना चाहिए था इसके बाद पदोन्नति पांच वर्ष बाद दिया जाना चाहिए था। रही बाद यदि डीपीसी की तो सिर्फ तीन ही कर्मचारियों के नाम पर क्यों सहमति बनाया गया जो कि संदेहास्पद स्थिति को निर्मित करता है। साथ मे और भी कर्मचारी कन्छेदी लाल मेहरा और कैलाश कुमार सेन के कैडर के है उनको भी पदोन्नत किया जाना चाहिए था। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर आनन-फानन में पदोन्नत और नियमित किया गया प्रतीत हो रहा है।

विभाग के अधिकारीयों ने सारे नियम ताक में रखकर चहेते कर्मचारी को फायदा पहुँचाया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि मदन विश्वकर्मा को सहायक ग्रेड तीन से सहायक ग्रेड दो पर पदोन्नत करने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के विभागीय पदोन्नति की बैठक 26 सितम्बर 2006 को हुई थी। जिसमें मदन विश्वकर्मा सहित विभाग के पांच अन्य अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नत करने के लिए इनके नामों पर मुहर लगाया गया। इसके पश्चात विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय स्थापना ने महज दो साल के भीतर विभाग के अधिकारीयों ने सारे नियम कायदे को ताक में रखकर 13 अक्टूबर 2006 को मदन विश्वकर्मा को सहायक ग्रेड तीन से सहायक ग्रेड दो पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया गया।

इसके बाद मदन विश्वकर्मा को फिर से पदोन्नत करने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारीयों ने पांच मई 2012 को पुनः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाया गया | जिसमे मदन विश्वकर्मा को सहायक ग्रेड दो से सहायक ग्रेड एक पर पदोन्नत करने के लिए सहमति बनी। तत्पश्चात संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के अधिकारी ने 18 जून 2012 को उक्त कर्मचारी को पदोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया।

भारत सरकार के कार्मिक विभाग का नियम

नियम की बात करे तो भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा 12 सितम्बर 2002 को जारी आदेश संख्या 85/ 2002 के मुताबिक मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरवर्ती मध्यदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति 01 नवम्बर 2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो को उसके नाम के सामने कैडर दर्शाया गया। उत्तरवादी मध्यदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य यथास्थिति 01 नवम्बर 2000 से ही सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जायेगा। नियम का उल्लेख करने का मकसद यह है कि यदि मदन विश्वकर्मा की तर्दथ नियुक्ति को पदोन्नत करते हुए नियमित करने के लिए 29 मार्च 2001 को यदि डीपीसी की बैठक हुई और 28 मई 2004 को कैसे नियमित करने का आदेश जारी किया गया। इस नियम के मुताबिक उक्त कर्मचारी की नियुक्ति और पदोन्नति ही फर्जी हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री और सचिव मौन

तत्संबंध में मदन विश्वकर्मा और अन्य के खिलाफ विभागीय जांच समिति के अभिमत तथा तथ्यों के आधार पर दो वर्ष बाद भी 25 साल से DHS में कार्यरत पदस्थ पदोन्नत लोगों के संबंध में शहर सत्ता संवादाता ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से फोन पर संपर्क किया तो वे उपलब्ध नहीं हुए। शहर सत्ता द्वारा तत्संबंध में प्राप्त दस्तावेज और विभागीय जांच समिति के अभिमत की प्रति भी वाट्सअप की गई और विभागीय पक्ष जानना चाहा तब भी कोई अधिकृत वर्जन समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हुआ था।

एक नजर में मदन विश्वकर्मा का फर्जीवाड़ा

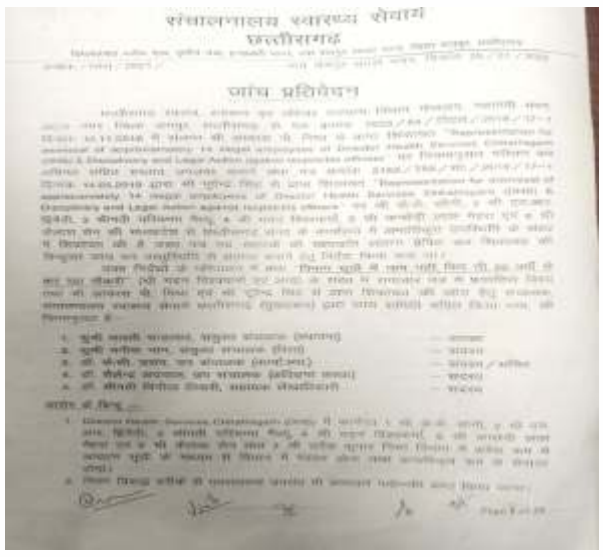

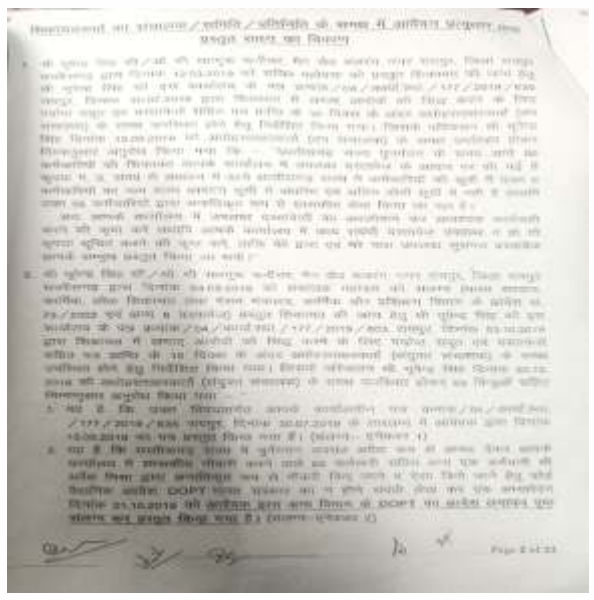

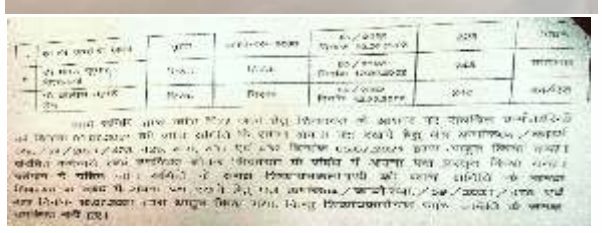

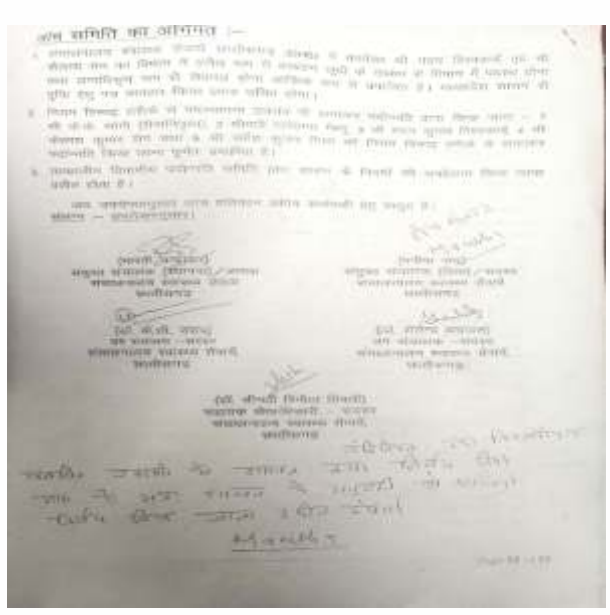

1. संविलियन आदेश मूल सेवा पुस्तिका में शासन द्वारा 2004 के आदेश में 2001 से नियमित किया जाने का उल्लेख है। ऐसे में 4 साल की वरिष्ठता का बेजा लाभ लिया।

2. तदर्थ नियुक्ति यानि कि श्रमिक दर पर बतौर भृत्य भर्ती हुई, फिर बाबू संवर्ग पदोन्नति और कहीं खुद को टीबी स्पेशलिस्ट बताया गया।

3. टीबी स्पेशलिस्ट या भृत्य पद से सहायक वर्ग 03, फिर 02, फिर सहायक वर्ग 01 हुआ अभी सहायक अधीक्षक पद पर है। अब एओ यानि प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति प्रतीक्षा में है। देखा जाये तो एक विवादित नियुक्ति वाले को DHS में 25 साल में पदोन्नत कौन करता रहा ?

4. इनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है उसमे प्रथम नियुक्ति आदेश, छत्तीसगढ़ में संविलयन आदेश, एमपी से छत्तीसगढ़ में आवंटित आदेश लेकिन इसमें कंटिंजेंसी पेड शब्द का उल्लेख नहीं जबकि कार्मिक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज में कंटिंजेंसी पेड का उल्लेख किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभागीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन अभिमत में अवैध रूप से आवंटन सूचि के माध्यम से विभाग में पदस्थ होना तथा अनधिकृत रूप से सेवारत होना प्रमाणित है। जो कि उनकी पदस्थापना, नियुक्ति और आवंटन को कटघरे में खड़ी करती है।

6. जांच समिति ने विशेष टिपण्णी में लिखा है कि मदन विश्वकर्मा के अंतिम राज्य आवंटन सूचि के पृष्ठ क्रमांक 248 में नाम है। लेकिन पदनाम, वेतनमान की जानकारी नहीं है।

7. राज्य आवंटन सूचि में सभी कैडर को एक क्रमांक दिया गया है एवं प्रत्येक पृष्ठ के अंत में जिस कैडर के अधिकारी-कर्मचारी की सूचि समाप्त होती है उस कैडर का नाम अंकित किया गया है। पृष्ठ क्रमांक 248 में सूचि के अंत में कैडर टीबी स्पेशलिस्ट अंकित है।

8. मदन विश्वकर्मा का प्रमोशन, नियुक्ति सभी रहस्यपूर्ण और कूटरचित है।

9. कंछेदी लाल का निधन, केके सोनी सेवानिवृत, बाकि 5 लोग सेवा में है।

10. सिर्फ सर्वेश मिश्रा की नियुक्ति, वेतनमान, पदोन्नति के सभी दस्तावेज है।

11. जाँच प्रतिवेदन के खिलाफ हाई कोर्ट बिलासपुर में WPS पिटीशन सर्विस लगाया है और कोर्ट से सशर्त स्थगन मिला है।

12. चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन सभी के नाम का जाँच प्रतिवेदन 25-01-2022 को शासन को भेजा गया है।

13. बजट शाखा में रहते हुए बिना विभागीय अनुमति के मदन विश्वकर्मा दुबई, थाईलैंड और नेपाल की 2-2 बार यात्रा कर चुके हैं।

14. DHS के विवादित बाबू की विदेश यात्रा का मामला विधानसभा में वर्ष 2024 में ध्यानाकर्षण में विधायक अनुज शर्मा ने उठाया था

15. मदन विश्वकर्मा की कैडर, पोस्टिंग और प्रमोशन के संबंध में मध्य प्रदेश और केंद्रीय कार्मिक विभाग नई दिल्ली से पुष्टि हेतु पत्र व्यवहार होना चाहिए भी फंडिंग को लेकर चिंता जता चुके हैं।

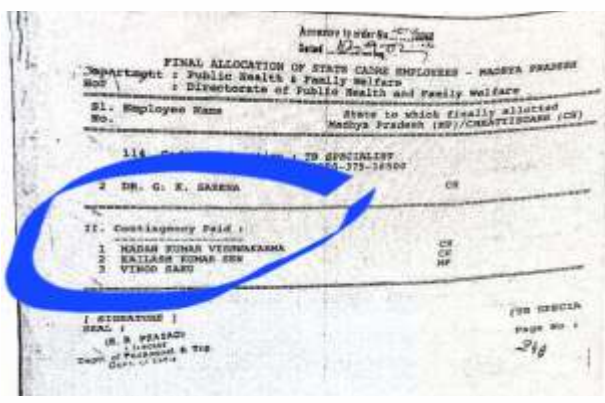

मेजर पनिशमेंट

- सीधे बर्खास्तगी,
- अर्जित वेतन, भत्ते की रिकवरी
- पुलिस में FIR दर्ज होगी
- कूट रचना, गलत दस्तावेज के लिए गिरफ़्तारी
- सजा का भी प्रावधान

जांच समिति में थे ये विभागीय अधिकारी

- 1. सुश्री भर्ती चंद्राकर, संयुक्त संचालक(स्थापना) (अध्यक्ष)
- 2. सुश्री मनीषा नाग, संयुक्त संचालक(वित्त) (सदस्य)
- 3. डॉ. केसी. उरांव, उप-संचालक (कार्या. स्था.) (सदस्य/सचिव)
- 4. डॉ. शैलेन्द्र अग्रवाल, उप-संचालक(अविज्ञप्त शाखा) (सदस्य)
- 5. डॉ. श्रीमती विनीता तिवारी, सहायक लेखाधिकारी (सदस्य)

आफत की बारिश : कवर्धा में पांच पर्यटक बह गए, एक की मौत

रायपुर/कवर्धा/बालोद। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तेज बारिश और बाढ़ के चलते प्रदेश में दुर्घटनाएं और क्षति की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रविवार को कवर्धा में एक दर्दनाक हादसे में 5 पर्यटक पुल पार करते समय बह गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक अब भी लापता है। बालोद में रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है, वहीं कई जिलों में तेज बहाव में मवेशियों के बहने के दृश्य भी सामने आए हैं।

रविवार को कवर्धा जिले के रानीदहरा जलप्रपात में घूमने आए मुंगेली जिले के 5 पर्यटक अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गए। यह हादसा पुलिया पार करते समय हुआ, जब बारिश के कारण जलस्तर अचानक बढ़ गया। हादसे में 45 वर्षीय नरेंद्र सिंह पाल, निवासी दाऊपारा (मुंगेली) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सृजल पाठक नामक युवक लापता है। तीन अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया है।

मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, SDRF की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर लापता युवक की तलाश कर रही है। तेज बारिश के चलते बालोद जिले के दल्ली राजहरा में हालात गंभीर हो गए हैं। खासकर वार्ड क्रमांक 04, 20, 22, 23, 24, सब्जी मंडी और चिखलाकसा के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। नाले में बहकर एक गाय के बहने का वीडियो सामने आया है, जिसने बारिश की भयावहता को उजागर किया। दल्ली राजहरा-अंतागढ़ रेल मार्ग पर ट्रैक जलभराव में डूब गया है, जिससे इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। राज्य के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

मानसून की अवधि लंबी रहने की संभावना

इस साल मानसून सामान्य से 8 दिन पहले 24 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि आमतौर पर यह 1 जून को पहुंचता है। इसके अनुसार, यदि मानसून 15 अक्टूबर को लौटता है, तो यह करीब 145 दिन की अवधि तक सक्रिय रह सकता है। यदि इस दौरान कोई ब्रेक (रुकावट) नहीं आती है, तो वर्षा की यह अधिक अवधि फसलों के लिए फायदेमंद भी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र

शुरुआत से अंत तक घमासान लोकतांत्रिक परंपराएं ध्वस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कुल 5 दिनों का रहा, लेकिन यह सत्र मात्र औपचारिक कार्यवाही नहीं, बल्कि तीखे राजनीतिक टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, निलंबन और वॉकआउट का मंच बन गया। मानसून सत्र में मुख्य रूप से विपक्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद संकट, आवास योजना, जल जीवन मिशन, घुसपैठ, CSR फंड और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने यहां तक कह दिया कि "पिछले 25 वर्षों की लोकतांत्रिक मर्यादा इस बार टूट गई है"।

पहला दिन

खाद और बीज संकट पर विपक्ष का हमला: पहले दिन प्रदेश में उर्वरक और बीज की भारी किल्लत को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायक वेल में आ गए। अध्यक्ष द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया।

राजस्व निरीक्षक परीक्षा में गड़बड़ी: भाजपा विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी, रिश्तेदारों को विशेष लाभ देने के आरोप लगाए और CBI जांच की मांग की। असंतोष के चलते विपक्ष ने वॉकआउट किया।

पुरानी योजनाओं पर सियासी खींचतान: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी सरकार की 96 योजनाओं में से 11 को बंद कर दिया गया है और 6 के नाम बदल दिए गए। मंत्री रामविचार नेताम ने दो टूक कहा—"हम पुरानी सरकार की योजनाएं क्यों ढोएं?"

दूसरा दिन

CSR फंड की पारदर्शिता पर सवाल: बस्तर में CSR फंड के उपयोग को लेकर विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता की मांग की। मंत्री ने नियमों के अनुसार खर्च की जानकारी दी, लेकिन विपक्ष ने असंतोष जताया।

जल जीवन मिशन पर आंकड़ों की बहस: भूपेश बघेल ने 21 लाख घरों में जल आपूर्ति के दावों को 'झूठा' करार दिया। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन विपक्ष ने बहस अधूरी बताते हुए वॉकआउट कर दिया।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर गंभीर आरोप: भाजपा ने रायपुर सहित अन्य स्थानों पर अवैध घुसपैठियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने रायपुर में 100 सीट वाले बोर्डिंग सेंटर की योजना की जानकारी दी।

रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग: अवैध रेत खनन के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष ने खारिज कर दिया, जिससे नाराज़ विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया।

तीसरा दिन

प्रधानमंत्री आवास योजना की विसंगतियां: नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने योजना में गड़बड़ी और दिव्यांगों को लाभ न मिलने का मामला उठाया। जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया।

मेकाहारा अस्पताल की खराब स्थिति: विधायक शेषराज हरवंश के सवाल पर मंत्री ने स्वीकार किया कि 161 में से 50 मशीनें बंद हैं और कई वर्षों से इन्हें चालू नहीं किया गया।

बिजली दरों में वृद्धि: विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया जो खारिज हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक बहस हुई। मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया गया।

चौथा दिन

DAP खाद की किल्लत पर फिर हंगामा: कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी करार दिया और मंत्री से इस्तीफा मांगा। नारेबाजी के चलते कुछ विधायकों को निलंबित किया गया।

हाउसिंग बोर्ड की नई नीति: सरकार ने घोषणा की कि अब 60% प्री-बुकिंग के बिना कोई परियोजना लॉन्च नहीं होगी।

भारतमाला भूमि घोटाले पर CBI जांच की मांग: भाजपा ने ईओडब्ल्यू जांच को अपर्याप्त बताते हुए CBI जांच की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया।

विधानसभा की परंपरा टूटी: अध्यक्ष रमन सिंह ने खुले मंच से कहा कि विपक्ष का व्यवहार लोकतांत्रिक गरिमा के विपरीत रहा और इससे परंपराएं टूट गईं।

पांचवां दिन

धान खरीदी, NGO अनुदान और दिव्यांग मुद्दों पर सरकार को घेरा: अंतिम दिन विपक्ष ने सरकार को तीन बड़े मोर्चों पर घेरते हुए तीखा हमला बोला।

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी बनी सत्र का राजनीतिक बिंदु: भूपेश बघेल के घर ED का छापा और उनके बेटे की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश बताया। बघेल ने कहा—"ये सब अडानी के खिलाफ हमारी आवाज दबाने की साजिश है।"

हसदेव अरण्य और आदिवासी मुद्दे: विपक्ष ने जंगलों की कटाई, आदिवासी विस्थापन पर सरकार की नीति को नाकाम बताते हुए बहिर्गमन किया।

आसमान से कहर बरपा मोबाइल पर गेम खेलते युवक की मौत

रायपुर/बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में शनिवार को मौसम का कहर मौत बनकर टूटा। तेज गरज-चमक के बीच आसमान से गिरी बिजली ने तीन लोगों की जान ले ली, वहीं आठ लोग घायल हो गए। रायपुर में एक युवक मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तभी बिजली उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर आ गिरी, जिससे धमाका हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर, बलरामपुर में खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर बिजली गिरी, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार दोपहर रायपुर के भावना नगर, खम्हारडीह थाना क्षेत्र में तीन युवक छत पर बैठे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे।

दोपहर लगभग 1 बजे अचानक आसमान से एक तेज चमक और आवाज के साथ बिजली गिरी, जो सीधा हाथ में पकड़े मोबाइल फोन पर आ लगी। बिजली गिरते ही मोबाइल जोरदार धमाके से फट गया। हादसे में यूपी के गोरखपुर निवासी सन्नी (उम्र लगभग 22 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य युवक बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सन्नी मजदूरी के सिलसिले में रायपुर आया हुआ था और भावना नगर इलाके में रह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है।

बलरामपुर में गाज गिरने से दो की मौत

दूसरी घटना बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बेलसर में घटी। यहां ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे, तभी शाम के वक्त अचानक आकाशीय बिजली ने खेत को चपेट में ले लिया। इस हादसे में मनेश्वर अगरिया (18) और सुवेश्वर नगेशिया (37) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिजली गिरने से 6 अन्य ग्रामीण घायल हुए, जिन्हें तत्काल शंकरगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया। घायलों में शामिल हैं: संतोष तिग्गा (40), सुशीला तिग्गा (35), संतोष अगरिया (24), धनेश्वर अगरिया (19), लोखनाथ (55), मनरखन (25), (सभी निवासी ग्राम बेलसर)। थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। विज्ञान कहता है कि जब बादलों में विपरीत चार्ज जमा होते हैं और वे आपस में टकराते हैं, तो इससे घर्षण उत्पन्न होता है। यह घर्षण ऊर्जा बनकर बिजली के रूप में धरती पर गिरती है।

एक टीचर के भरोसे पांच कक्षा हेडमास्टर, प्यून, कुक भी खुद

भिलाई/धमधा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का एक यथार्थ चेहरा – जहाँ एक शिक्षक ही प्रधानपाठक है, वही प्यून है, वही रसोई का राशन लाता है, और वही पांच अलग-अलग कक्षाओं को एकसाथ पढ़ाता है। धमधा ब्लॉक के शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बताती है कि शैक्षिक सुधारों के दावे ज़मीन पर अब भी अधूरे हैं। शिक्षक रामप्रकाश पटेल ही यहां के इकलौते शिक्षक हैं। दोपहर ढाई बजे जब कक्षा में पहुँचे तो बोर्ड चार हिस्सों में बंटा था— पहली-दूसरी के लिए बारहखड़ी, तीसरी के लिए "गाय" पर रचना, चौथी के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र, और पांचवीं के लिए अंग्रेजी और गणित। पटेल सप्ताह में तीन दिन बड़ी कक्षाओं (4-5) और बाकी दिन छोटी कक्षाओं (1-3) को पढ़ाते हैं। जिनकी क्लास नहीं होती, उन्हें अभ्यास कार्य देकर चुपचाप बैठा दिया जाता है।

अगार गांव में यहां स्थिति और भी चिंताजनक है। सुबह 10:40 बजे स्कूल में कोई नियमित शिक्षक मौजूद नहीं था। बच्ची नैना जोशी हाथ में छड़ी लेकर ब्लैकबोर्ड पर अंग्रेजी के अक्षर पढ़ा रही थी। बाकी छात्र दोहरा रहे थे। 82 बच्चों वाले इस स्कूल में दो वर्षों से कोई नियुक्त शिक्षक नहीं है। पास के मिडिल स्कूल से शिक्षक रूपेन्द्र कुमार साहू कभी-कभी आकर पढ़ाते हैं, लेकिन न तो किताबें मिलीं, न नियमित कक्षा।

आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों का प्रदर्शन तेज

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर दुर्ग में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। करीब 600 संविदा शिक्षक सड़कों पर उतरे और सरकार से स्थायी नियुक्ति और वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांगें स्पष्ट और सीमित हैं: संविलियन कर स्थायी नियुक्ति एवं नियमित वेतन वृद्धि का प्रावधान। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद, अब तक कोई ठोस नीति या आदेश सामने नहीं आया है।

पाठशाला बनी 'संघर्षशाला'

मैनपाट। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देशभर में चर्चित मैनपाट में शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई कड़वी और चौंकाने वाली है। जिस क्षेत्र में हाल ही में तीन दिन तक छत्तीसगढ़ सरकार की मौजूदगी रही, जहां भाजपा का बड़ा प्रशिक्षण शिविर हुआ, उसी इलाके में बच्चे झोपड़ी और किचन में पढ़ने को मजबूर हैं।

मैनपाट ब्लॉक के कुदारीडीह जंगलपारा में संचालित प्राथमिक शाला की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन आज तक भवन नहीं बन पाया। स्कूल पहले आंगनबाड़ी के भवन में संचालित था, लेकिन छत टूटने के बाद बच्चों की क्लास अब स्कूल के किचन शेड में लगाई जा रही है। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। शिक्षकों का कहना है कि भवन की मांग कई बार ब्लॉक और जिला अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। दूसरा मामला मैनपाट विकासखंड के सुपलगा गांव का है, जहां जरहाडीह प्राथमिक शाला को किराए की एक झोपड़ी में चलाया जा रहा है। विभाग हर महीने 1,000 रुपये किराया चुका रहा है। यहां भी भवन नहीं है। सुपलगा के स्कूल के लिए 2016 में भवन स्वीकृत हुआ था। निर्माण एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते न तो भवन बना और न ही विभाग ने मॉनिटरिंग की। शौचालय का निर्माण भी अधूरा छोड़ दिया गया।

साप्ताहिक शहर सत्ता

अबूझमाड़ एनकाउंटर : 48 लाख के छह ईनामी नक्सली ढेर, कमांडर राहुल मृत

बड़े लीडर्स को सुरक्षा देती थी यूनिट; शव-हथियारों का जखीरा लेकर लौटी फोर्स

शहर सत्ता/नारायणपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में 48 लाख रुपए के 6 नक्सली मारे गए हैं। इन सभी के शवों समेत हथियारों जा जखीरा लेकर फोर्स लौट आई है। मारे गए नक्सली में PLGA प्लाटून नंबर 1 का कमांडर राहुल पुनेम समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सली नक्सल संगठन के बड़े लीडरों के लिए सुरक्षा देते थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचाने का काम करते थे। ये नक्सल संगठन में PLGA प्लाटून नंबर के बेस्ट फाइटर्स थे। 18 जुलाई को जवानों ने इनके गढ़ में घुसकर इन्हें घेरकर मारा है। मौके से स्नाइपर, AK-47, इंसास और SLR जैसे राइफल बरामद किया गया है।

अबूझमाड़ के परिया-काकुर इलाके में हुई मुठभेड़

बारिश के मौसम में भी माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून जारी है। पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के परिया और काकुर इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की इसी सूचना के बाद DRG, STF और BSF के जवानों को मौके के लिए निकाला गया था। 18 जुलाई की दोपहर पुलिस का नक्सलियों से सामना हुआ और उधर से फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जिसके बाद 19 जुलाई की शाम को मारे गए नक्सलियों के शव समेत भारी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद कर फोर्स लौट आई।

SP बोले- संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया

नारायणपुर SP रॉबिंसन गुरिया के मुताबिक 17 जुलाई को संयुक्त अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें नारायणपुर, कांकेर, बस्तर और कोंडागांव जिलों के DRG, STF और BSF की 129वीं, 133वीं व 135वीं बटालियन शामिल थी। 18 जुलाई 2025 की दोपहर से सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही।

IG ने कहा- 6 महीने में मारे गए 204 नक्सली

बस्तर IG सुंदरराज पी ने कहा कि पूरे बस्तर संभाग में प्रतिबंधित और अवैध माओवादी संगठन CPI (Maoist) के खिलाफ एक सशक्त अभियान जारी है। साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही 204 नक्सली अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं।

छत्तीसगढ़ में भूमि-अधिग्रहण प्राधिकरण गठन करने का आदेश

शहर सत्ता/रायपुर/बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी थी। सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी बाबूलाल ने एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि राज्य में सालों से भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण का गठन नहीं हो सका है। इसके चलते मुआवजा और ब्याज से जुड़ी सैकड़ों अर्जियां अधर में लटकी हुई हैं। इससे प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता या अन्य प्रभावित व्यक्ति मुआवजा या ब्याज का दावा करने से वंचित नहीं किए जाएंगे। यानी उनके हक अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने दिए गए निर्देशों का पालन किया या नहीं। याचिकाकर्ता ने पूर्व में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बताया कि राज्य बनने के बाद यहां प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है।

तकनीकः पावर टिलर बन रहा है बदलाव का आधार

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब जैविक खेती के साथ-साथ आधुनिक खेती के उपकरण को अपनाने के लिए भी तेजी से आगे आ रहा है। जिला प्रशासन ने हाल ही में यहां के 75 प्रगतिशील किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों को पावर टिलरों का वितरण किया है। सबसे बड़ी बात है कि इन आधुनिक खेती के उपकरणों का उपयोग व्यक्तिगत खेती में ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से इनके सामूहिक उपयोग मॉडल पर भी जोर दिया गया है, जिससे गांव के अन्य किसान भी इसका लाभ उठा सकें। पावर टिलर के माध्यम से किसान खेतों की गहरी जुताई करने के साथ-साथ मिट्टी को बारीक करने और जैविक खादों को समरस रूप से मिलाने में कर रहे हैं। जहां पहले पारंपरिक हल से खेत की जुताई में दो से तीन दिन लगते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। पावर टिलर का आकार छोटा और संचालन सरल होने के कारण यह छोटे जोत के किसानों के लिए भी उपयुक्त है। ग्राम हीरानार के किसान लूदरुराम और ग्राम कासौली के सुरेश नाग बताते हैं कि पावर टिलर के उपयोग से खेती करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। समय की बचत हो रही है। उत्पादन में भी सुधार देखने को मिल रहा है। यह मल्टीपरपज मशीन न केवल जुताई के काम आती है, बल्कि मिट्टी पलटने, कतार बनाने, खाद मिलाने और ट्रॉली से परिवहन जैसे कार्यों में भी सहायक है।

जगी नई उम्मीद : थैलेसीमिया पीड़ित 30 बच्चों को मुफ्त जांच और उपचार

शहर सत्ता/रायपुर। जिला अस्पताल पंडरी में थैलेसीमिया से जूझ रहे मासूम बच्चों के लिए 'प्रोजेक्ट जीवन' के अंतर्गत निशुल्क परामर्श और उपचार हेतु विशेष शिविर का सफल आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य उन बच्चों को राहत देना है, जो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण लगातार रक्त चढ़वाने को विवश हैं। शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों को मुफ्त इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन देने की पहल की गई। शिविर में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. विकास दुआ और रक्त विकार विशेषज्ञ व ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. परमिंदर पाल सिंह ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दीं। शिविर में 12 वर्ष से कम आयु के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का निशुल्क परीक्षण, परामर्श और उपचार किया गया। मरीजों और उनके परिजनों को थैलेसीमिया की रोकथाम, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस शिविर की सबसे महत्वपूर्ण पहल रही निशुल्क HLA जांच, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की संभावना का पता लगाया जाएगा। जिन बच्चों की जांच में उपयुक्त मैच पाया जाएगा, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट शासन की ओर से पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा। शिविर में कुल 30 मरीजों ने भाग लिया और 40 से अधिक HLA सैंपल जांच हेतु एकत्रित किए गए। इस अवसर पर परिजनों को आगे के उपचार और देखभाल से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी गई। शिविर के आयोजन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. संतोष भंडारी, प्रोजेक्ट जीवन की नोडल अधिकारी डॉ. श्वेता सोनवानी, कंसल्टेंट मिथलेश सोनबेर, डॉ. राखी चौहान और जिला अस्पताल के अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल रहे।

जशपुर जिले के 48 मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 2.03 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर जिले के 48 प्राचीन और जनआस्था से जुड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 3 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है। इससे जशपुर जिले की धार्मिक पहचान को सहेजने के साथ-साथ क्षेत्रीय पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंदिरों के विकास, संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर यह कार्य धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर की पावन धरती सदैव से श्रद्धा, संस्कृति और आस्था का केंद्र रही है। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार केवल संरचना का नवीनीकरण नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और आत्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण है। मेरा संकल्प है कि हर ग्राम का धार्मिक स्थल सुव्यवस्थित हो, जिससे वहां भक्ति का वातावरण बने।

खारंग डेम और खपरी जलाशय हुए लबालब, मनियारी, झुमका और छिरपानी में 90 फीसद से अधिक पानी

राज्य के सिंचाई जलाशयों में 50 फीसद जलभराव

शहर सत्ता/रायपुर। जल संसाधन विभाग द्वारा 19 जुलाई को जारी टैंक गेज रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रमुख सिंचाई जलाशयों में अब तक 49.78 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। बिलासपुर स्थित खारंग डेम और दुर्ग जिले का खपरी जलाशय लबालब हो गया है। राज्य के कुल 46 प्रमुख जलाशयों में से झुमका जलाशय में 98.84 प्रतिशत, मनियारी जलाशय 90 प्रतिशत से अधिक, जबकि छरपानी जलाशय में 91 प्रतिशत से अधिक जलभराव हुआ है।

मिनीमाता बांगो डेम (कोरबा) में अब तक 52.78 प्रतिशत जलभराव हुआ है, रविशंकर सागर (धमतरी) में 53.26 प्रतिशत, तांडुला डेम (बालोद) में 29.29 प्रतिशत, दुधावा डेम में 21.87 प्रतिशत, सिकासार डेम में 45.21 प्रतिशत, सोंढूर में 23 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली डेम में 21.57 प्रतिशत, कोडार डेम में 38.11 प्रतिशत, केलो डेम में 30.96 प्रतिशत जलभराव हुआ है। राज्य के 12 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में शामिल खारंग डेम (बिलासपुर) में 100 प्रतिशत जलभराव दर्ज किया गया है, जो सर्वाधिक भराव वाले जलाशयों में शामिल है। मनियारी डेम (मुंगेली) में जल स्तर 93.17 प्रतिशत तक पहुंच गया है, छोटे जलाशयों जैसे झुमका डेम (कोरिया) और छिरपानी (कबीरधाम) में क्रमशः 98.84 प्रतिशत और 91.14 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। इसी तरह अरपा भैंसाझार (बिलासपुर) और मायना (कांकेर) जैसे जलाशयों में 30 प्रतिशत से भी कम, गोंदली डेम (बालोद) में 30.24 प्रतिशत और कोसारटेडा डेम (बस्तर) में 42.57 प्रतिशत जलभराव हुआ है।

50% से अधिक जलभराव वाले जलाशय

1	मिनीमाता बांगो डेम (कोरबा)	52.78%
2	रविशंकर सागर डेम (धमतरी)	53.26%
3	रूसे डेम	54.47%
4	मोंगरा बैराज	62.62%
5	सुतियापात जलाशय	67.74%
6	श्याम डेम (सरगुजा)	69.38%
7	कर्रानाला बैराज	72.64%
8	सुखा नाला बैराज	72.95%
9	पिपरिया नाला डेम	77.64%
10	किंकारी नाला	80.31%
11	घोंघा जलाशय	82.84%
12	खमारपकुट डेम	86.11%
13	छरपानी जलाशय (कबीरधाम)	91.14%
14	मनियारी डेम (मुंगेली)	93.17%
15	झुमका जलाशय (कोरिया)	98.84%
16	खारंग डेम (बिलासपुर)	100%
17	खपरी जलाशय (दुर्ग)	100%

संपादकीय

● सुकांत राजपूत

अच्छाई और बुराई...

प्रकृति में विकास भी बुद्धिमानी से होता है। एक बरगद का पेड़ एक किलोमीटर ऊंचा नहीं हो जाता, भले ही वह 500 साल तक जीवित रहे। जंगल में शेर राजा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती कि जंगल में केवल शेर ही रहते हों। प्रकृति में अनियंत्रित विकास दुर्लभ है, क्योंकि यह सिस्टम को अस्थिर करता है। एकमात्र जगह जहां हम असीमित, अनियंत्रित विकास देखते हैं, वह है बीमारी। वास्तव में, यह कैंसर की परिभाषित विशेषता है। छत्तीसगढ़ की सियासत कमोबेश ऐसी प्रकृति से इतर हो चुकी है।

खासकर भाजपा की प्रतिस्पर्धी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में भी कई ऐसे बरगद हैं जो अमर बेल की तरह हैं। निरंकुश नेतृत्व और कथित भ्रष्ट आचरण के कारण छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बघेल अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए कांग्रेस की बची-खुची साख को दांव पर लगा रहे हैं, जबकि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का उन्हें दिल से कितना समर्थन मिल रहा है यह दल के नेता प्रश्न करते हैं। निरंकुश नेतृत्व और कथित भ्रष्ट आचरण के कारण छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर काले बादल मंडरा रहे हैं। अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बड़े नेता बेटे की गिरफ़्तारी से ज्यादा जन्मदिन में अरेस्ट करने को लेकर संवेदनशील हैं। समर्थक इसे आपदा में अवसर मानते हुए गिरफ्तार बिट्टू को नया उभरता नेता साबित करने पर तुले हैं।

महंत को अब यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह पार्टी के उन नेताओं को साथ लेकर चलें, जो बघेल को हटाना चाहते हैं। अब शायद उन्हें भी यह समझ में आने लगा है कि सिर्फ भूपेश बघेल का परिवार ही छत्तीसगढ़ नहीं है, जैसा वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंतरिक कलह और उनके बेटे चैतन्य की ईडी द्वारा गिरफ्तारी, कांग्रेस के लिए एक गंभीर संकट बन गई है, जिससे न केवल राज्य इकाई, बल्कि गांधी परिवार समेत केंद्रीय नेतृत्व भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस और गांधी परिवार अनिच्छा से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को चरणदास महंत की आवाज़ में आत्मविश्वास की कमी थी, जब वह कांग्रेस की एकता को लेकर पत्रकारों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर पार्टी में इतनी एकता है तो 12 बजे शुरू हुई बैठक ढाई घंटे तक क्यों चली? मज़े की बात यह है कि महंत ने बघेल की तरह केवल एक औद्योगिक घराने को घसीटने के बजाय सभी बड़े निवेशकों का नाम लिया। यह साफ संकेत है कि वह बघेल की कठपुतली नहीं हैं। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हालिया रायपुर दौरे में नेताओं से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की यह अपील पार्टी की बिखरी हुई स्थिति को उजागर करती है।

सत्ता में साझेदारी से बघेल का इनकार और वरिष्ठ नेताओं को व्यवस्थित रूप से किनारे लगाने से पार्टी का एक बड़ा वर्ग खुद को अलग-थलग महसूस कर रहा है। स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके प्रसिद्ध मतभेद और गहराते जा रहे हैं। इस असंतोष की जड़ में टीएस सिंह देव के साथ हुआ व्यवहार भी है। अच्छे हैं कि बुरे छवि सँवारने और विवादों को संभालने में ही पार्टी उलझी रहती। कांग्रेस आलाकमान हाल के चुनावी झटकों जिसमें विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में खराब प्रदर्शन शामिल है, से जूझ रहा है। अब उसे तुरंत जन-केंद्रित मुद्दों पर ध्यान देना होगा।

खुद को जांच से बचाने के लिए अडानी को बार-बार निशाना बनाने के बघेल के जुनून ने जनता की गंभीर चिंताओं से ध्यान भटका दिया है। हालांकि कई मतदाता कथित घोटालों की जटिलताओं को नहीं समझ पाते, एक मुद्दा बहुत गहराई से गूंज रहा है: नकली और घटिया शराब का प्रसार। मतदाता रोज़गार के अवसर और ठोस विकास चाहते हैं न कि वन संरक्षण पर केवल बयानबाज़ी, जबकि कोल इंडिया की सहायक और निजी कंपनियाँ वर्षों से वनों की कटाई कर रही हैं। मजे की बात इन खदानों को मंज़ूरी खुद बघेल सरकार ने दी थी। कांग्रेस को अब अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी होगी और बघेल परिवार के हितों से ऊपर शासन को प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि बहुत जल्द यह परिवार अपनी जमा संपत्ति बचाने के लिए कानूनी लड़ाइयों में फंसता दिख रहा है।

मानसून सत्र : सवालों से बचने की कोई सूरत नहीं

डेरेक ओ ब्रायन

संसद का मानसून सत्र अगले सप्ताह शुरू हो रहा है। इसकी तारीखों का ऐलान 45 दिन पहले ही हो गया था, जबकि अमूमन यह 18 से 20 दिन पहले होता है। समय से इतना पहले तारीखों की घोषणा का कारण स्पष्ट है।

सरकार संसद के विशेष सत्र से बचना चाहती है और लोकसभा व राज्यसभा में ऐसी चर्चा को टालना चाहती है, जिसमें उसे पहलगाम, पुंछ, राजौरी पर तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। दिसंबर 2023 के बाद से ही सरकार विपक्ष द्वारा प्रस्तावित एक भी चर्चा को अनुमति देने से बचती रही है। ऐसे में 21 दिन के आगामी सत्र से हम क्या अपेक्षा करें?

इस सत्र में संसद के दोनों सदनों में 21-21 घंटों के प्रश्नोत्तर सत्र होंगे और सवालों से बचने की कोई सूरत नहीं है। दोनों सदनों में प्रतिदिन एक घंटे का प्रश्नकाल मंत्रियों की जवाबदेही तय करेगा। उन्हें उत्तर देना ही होंगे, फिर चाहे वे तारांकित सवालों के मौखिक जवाब हों या अतारांकित के लिखित जवाब। संसद में हर दिन औसतन नौ सवालों के जवाब मौखिक दिए जाते हैं, जबकि 400 से अधिक के लिखित उत्तर प्राप्त होते हैं। चूंकि बीते डेढ़ वर्षों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के नोटिसों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए सिर्फ प्रश्नकाल ही इकलौता ऐसा उपकरण रह जाता है, जिसकी मदद से हमारे संसदीय लोकतंत्र के तहत सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यहां 2025 के बजट सत्र में पूछे गए कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में सरकार द्वारा दिया गया जवाब एक कहानी बयान करता है।

1. अटल पेंशन : मल्लिकार्जुन खरगे के सवाल के जवाब में खुलासा हुआ कि योजना की शुरुआत से अब तक 1.11 करोड़ खाते बंद हो चुके हैं। 1 अक्टूबर 2022 से नियमों में संशोधन कर आयकरदाताओं को योजना के लिए अपात्र कर दिया गया।

2. पीएम इंटर्नशिप योजना : टीएमसी के प्रकाश चिक बराइक के सवाल से खुलासा हुआ कि योजना के पहले चरण में विज्ञापित 1.27 लाख अवसरों में से महज 28 हजार 141 आवेदकों ने इंटर्नशिप स्वीकारी।

3. उड़ान योजना : प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना-उद्धव ठाकरे) के सवाल के जवाब में बताया गया कि योजना के तहत 619 रूट संचालित किए गए थे, जिनमें से 48% नॉन-ऑपरेशनल हैं। 114 मार्ग तो योजना के तीन साल पूरे होने से पहले ही बंद कर दिए गए थे।

4. समग्र शिक्षा अभियान : डॉ. जॉन ब्रिटस (माकपा) का सवाल स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना पर था। जवाब में बताया गया कि तमिलनाडु के लिए 2152 करोड़, बंगाल के लिए 1745 करोड़ और केरल के लिए 329 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। लेकिन इनमें से किसी राज्य को धनराशि जारी नहीं की गई।

5. केंद्रीय विद्यालयों में रिक्त पद : रामजीलाल सुमन (सपा) के सवाल

पर सरकार ने बताया कि दिसंबर 2024 तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में 8977 पद रिक्त थे। इनमें 7414 पद (83%) शैक्षणिक थे।

6. साइबर हमले : संजीव अरोरा (आप) के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 2020 से 2024 के बीच देश में साइबर सुरक्षा संबंधी 75.86 लाख से अधिक घटनाएं हुईं। 2020 की तुलना में ये 76% की वृद्धि थी। वहीं नीरज डांगी (कांग्रेस) के सवाल पर सरकार ने बताया 2022 से 2023 के बीच डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के मामले 334% बढ़े हैं। 2022 के 277 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में धोखाधड़ी 1457 करोड़ रुपए की हो गई।

7. पीएम-कुसुम : यह योजना किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। बजरंग मनोहर सोनवणे (राकांपा-शरद पवार) के सवाल से पता चला कि 10 हजार मेगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों के स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में 431 मेगावॉट के संयंत्र ही स्थापित हो पाए हैं।

8. कर्ज माफी : अमरा राम (माकपा) ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कर्ज माफी पर सवाल पूछा। पता चला कि 2014 से 2023 के बीच 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफ किए गए हैं। इनमें से 57% बड़े उद्योगों और सेवाओं के हैं। वहीं इस स्तम्भकार ने सरकार से किसानों पर बढ़ते कर्ज पर सवाल किया। सरकारी डेटा से खुलासा हुआ कि हर कृषक-परिवार पर औसतन बकाया ऋण राशि 74 हजार रुपए थी। कर्ज का उच्चतम स्तर आंध्रप्रदेश में 2.45 लाख रुपए है। इसके बाद केरल में 2.42 लाख रुपए, पंजाब में 2.03 लाख रुपए, हरियाणा में 1.83 लाख रुपए और तेलंगाना में 1.52 लाख रुपए है।

बीते डेढ़ वर्षों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के नोटिसों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में प्रश्नकाल ही इकलौता ऐसा उपकरण रह जाता है, जिससे संसदीय लोकतंत्र के तहत सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख के सहायक-शोधकर्ता आयुष्मान डे और धीमंत जैन हैं)

श्रीकृष्ण की सीख- हर कर्म का फल जरूर मिलता है

कुरुक्षेत्र के जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। जीवन में कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने कर्म धर्म के मुताबिक करते रहना चाहिए। कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता है, वह सही समय आने पर हमें अवश्य मिलता है। श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और कर्म का महत्व समझाया। स्वयं श्रीकृष्ण ने भी अपने कर्मों के परिणाम स्वीकार किए। श्रीकृष्ण की लीलाएं जब पूरी हो गईं, तब एक दिन वे अकेले जंगल में विश्राम की मुद्रा में लेटे थे, तब एक शिकारी का बाण उनके पैर पर लगा और इसके बाद वे अपने धाम लौट गए। ये कर्म के चक्र की पूर्णता का प्रतीक है, कर्म भूलता नहीं।

कर्म का नियम है हर क्रिया का फल जरूर मिलता है

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। श्रीकृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का मार्गदर्शन किया, युद्ध की रणनीति बनाई और कई बार पारंपरिक नियमों को भी तोड़ा। धर्म की विजय के लिए उन्होंने कई तरह की लीलाएं रचीं। गांधारी के सभी पुत्र महाभारत युद्ध में मारे गए। दुखी होकर गांधारी ने श्रीकृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह कौरव वंश खत्म हुआ है, ठीक इसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी खत्म होगा। श्रीकृष्ण ने क्रोध नहीं किया, बल्कि इस शाप को भी स्वीकार किया, क्योंकि वे हमें संदेश देना चाहते थे कि हर कर्म की प्रतिक्रिया निश्चित है। श्रीकृष्ण की नीतियों की वजह से ही पांडवों ने कौरव वंश को खत्म कर दिया और धर्म की स्थापना हुई। इसके बदले में श्रीकृष्ण ने गांधारी का शाप स्वीकार किया। श्रीकृष्ण ने हमेशा निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है। भगवान ने कभी भी राजपाट, यश, कीर्ति, वंश के लिए कभी मोह नहीं किया, उन्होंने सिर्फ धर्म के अनुसार कर्म पर ही ध्यान दिया। युद्ध में श्रीकृष्ण ने जो कर्म किए, उनकी वजह से उनके पूरे वंश को गांधारी का शाप झेलना पड़ा। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने हमें वही संदेश दिया है जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। फल की चिंता छोड़ दो, लेकिन जब फल मिलता है तो उसे सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार जरूर करना चाहिए।

कर्म और नियति, एक ही चक्र के अलग-अलग अंग हैं

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। उन्होंने स्वयं ये सत्य अपने अंतिम समय से सिद्ध किया, जब जरा नाम के शिकारी ने श्रीकृष्ण के पैर में बाण मारा। जरा पुराने जन्म में बालि वानर था। विष्णु जी के अवतार राम ने बालि को छिपकर बाण मार था। त्रेतायुग के इस कर्म का फल द्वापर युग में विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण को मिला।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-नागपंचमी लकठाथे तहाँ ले नगडेवन बजा के अपन झपोली ल उघार के नागदेवता के दरस करावत कतकों सपेरा मन दिख जाथें जी भैरा.

-हव जी कोंदा.. नाग ल हमर संस्कृति म देवता बरोबर माने गे हवय न.. तभे तो उँकर पूजा के घलो परंपरा हे हमर इहाँ.. तोला सुरता हे नहीं.. लइका राहन त सिलेट/पट्टी म नाग के छापा बना के स्कूल जावन अउ उहाँ फूल पान दूध चघा के पूजा करन.

-सुरता हे संगी.. लइकई के आनंद ल कइसे भुला पाबोन.

-सही आय.. साँप मन हमर खेती-किसानी म घलो संगवारी बरोबर होथें.. खेत म बोवाय फसल ल कतकों किसम के कीरा-मकोरा अउ मुसवा-उसवा मनला खाके बचाथें.. कतकों किसम के रोग-राई ले बचाय बर बनइया दवई मन म घलो एकर योगदान होथे.

-हव.. बहुउपयोगी होथे साँप मन हमर जिनगी म तभे तो भगवान भोलेनाथ ह वोला अपन गर के माला बना लिए हे, त भगवान विष्णु ह अपन शयनशैय्या.

-सही आय जी.. फेर बरखा के मौसम म साँप-डेडू दिख जावय त वोकर ले सावचेती रहना घलो जरूरी होथे.. नहीं ते खबर तो सुनेच ले मिलत रहिथे के फलाना जगा साँप चाबे म कोनो मरगे कहिके.

साप्ताहिक शहर सत्ता

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार मोदी सरकार

ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस और AAP ने की बड़ी मांग

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 'ऑपरेशन सिंदूर' समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. उन्होंने यह बात उस सर्वदलीय बैठक में कह रहे थे जो मानसून सत्र से पहले बुलाई गई थी. रिजिजू ने सभी दलों से अपील की कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए.

ट्रंप के दावे पर भी चर्चा के लिए तैयार सरकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया बयान को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई और संघर्ष विराम कराया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा, सरकार संसद में इस मुद्दे पर उचित जवाब देगी. संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को सांसदों का अच्छा-खासा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं.

विपक्ष के निशाने पर पहलगाम हमला

विपक्ष ने बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जिन्हें वह संसद में जोर-शोर से उठाने वाला है. इनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों का आरोप, हाल ही में हुआ पहलगाम आतंकी हमला और ट्रंप का विवादित दावा प्रमुख हैं. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी तीन प्रमुख मांगें लेकर संसद पहुंचेगी:

आम आदमी पार्टी ने उठाया 'चुनावी घोटाले' का मुद्दा

आप सांसद संजय सिंह ने बैठक में SIR प्रक्रिया को "चुनावी घोटाला" करार देते हुए कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान मध्यस्थता संबंधी बयानों पर भी चिंता जाहिर की.

सर्वदलीय बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल

यह बैठक राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई. सरकार की ओर से किरन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाग लिया. बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, डीएमके के टीआर बालू, आरपीआई (A) के रामदास अठावले शामिल हुए.

पाकिस्तान को फिर सताने लगा भारत की एयरस्ट्राइक का डर

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन The Resistance Front (TRF) पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है. भारत की संभावित एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान सतर्क नजर आ रहा है. यही वजह है कि उसने अपनी एयरस्पेस में एक हफ्ते के लिए नोटम (NOTAM) जारी कर दिया है. पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, 16 से 23 जुलाई तक सेंट्रल सेक्टर की एयरस्पेस पूरी तरह बंद रहेगी. वहीं 22 और 23 जुलाई को दक्षिणी पाकिस्तान की हवाई सीमा भी बंद की गई है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे मिलिट्री एक्सरसाइज या मिसाइल परीक्षण बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में चीनी कार्गो विमानों की पाकिस्तान में आवाजाही देखी गई थी. इससे यह आशंका और मजबूत हो गई है कि चीन ने पाकिस्तान को नई सैन्य तकनीक, हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए हैं. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव आ गया है.

जांच से पहले निष्कर्ष न निकालें AAIB पर रखें भरोसा: नायडू

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने रविवार (20 जुलाई, 2025) को कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना को लेकर सरकार को किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए. किंजारापु ने कहा, 'मुझे दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और उनके काम पर पूरा भरोसा है. उन्होंने पूरे ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने और भारत में ही डेटा उपलब्ध कराने का सराहनीय काम किया है. इसी के साथ ही किंजारापु ने पश्चिमी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे मीडिया जिस तरह का लेख प्रकाशित कर रहे हैं, उनमें कोई गलत मंशा हो सकती है.

डेटा के लिए विदेश भेजा जाता है ब्लैक बॉक्स

उन्होंने आगे कहा कि जब भी विमान दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त पाया जाता था तो डेटा प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा विदेश भेजा जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि एएआईबी ने सबकुछ यहीं डिकोड कर लिया. ये भारत देश के लिए बड़ी सफलता है. मंत्री किंजारापु ने कहा कि अभी जांच से पहले कोई भी निष्कर्ष निकालना गलत होगा और अभी इसपर कोई टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए. सुरक्षा के लिहाज से जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.

आंध्र प्रदेश में 3200 करोड़ का शराब घोटाला

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश पुलिस ने शनिवार (19 जुलाई, 2025) को वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद मिधुन रेड्डी को गिरफ्तार किया है. सांसद मिधुन रेड्डी की गिरफ्तारी राज्य में पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित 3,200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में हुई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसद मिधुन रेड्डी राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के राजमपेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. शराब घोटाला मामले की जांच आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है.मिधुन रेड्डी शराब घोटाला मामले की पूछताछ में शामिल होने के लिए शनिवार (19 जुलाई) को सुबह में विजयवाड़ा पहुंचे थे. इसके बाद एसआईटी ने सांसद रेड्डी से दिनभर कई घंटों तक पूछताछ की. इसके बाद एसआईटी ने शाम साढ़े सात बजे विजयवाड़ा से ही सांसद मिधुन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया. आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी की पुष्टि की।

मेरे हिसाब से पार्टी नहीं देश सर्वोपरि : शशि थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने पार्टी से चल रहे मतभेदों पर खुलकर अपनी बात रखी. ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार का समर्थन करने वाले थरूर ने कहा कि नेताओं को दल की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए. थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि अगर भारत ही मर जाएगा तो फिर कौन जिंदा बचेगा?

कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि आज कोच्चि में हाई स्कूल के छात्र ने मुझसे एक जरूरी सवाल पूछा. हालांकि मैं सार्वजनिक रूप से ऐसी चर्चाओं से दूर रहता हूं, लेकिन मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसे लोग कहते हैं कि वह अपनी पार्टियों का सम्मान करते हैं तो हमारे कुछ कायदे और विश्वास होते हैं जो हमें हमारी पार्टियों से जोड़े रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हमें अन्य दलों और सरकार के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है.

शशि थरूर ने कहा कि कभी-कभी हमारे कुछ कामों या बयानों से पार्टी को लगता है कि ये उनके प्रति वफादारी को कम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत सर्वोपरि है. राजनीतिक पार्टियां भी राष्ट्र को बेहतर बनाने का ही माध्यम हैं. इसलिए मेरे विचारों में आप चाहें जिस भी पार्टी में हों उसका मकसद एक बेहतर भारत का निर्माण ही होना चाहिए.

जेलेंस्की के नरम पड़े तेवर, पुतिन को सीजफायर का ऑफर

नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार हैं और यह बातचीत अगले सप्ताह आयोजित की जा सकती है. यह बयान उस समय आया है जब रूस-यूक्रेन युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों को मानवीय, सैन्य और आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो चुका है. जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के साथ सीजफायर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. अगर ईमानदारी से बातचीत होगी तो यूक्रेन भी गंभीरता से शामिल होगा. इस बयान के बाद दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य देशों की प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी बताया कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के समन्वय पर गंभीरता से कार्य कर रही है।

क्या दूध भी नॉन-वेज होता है?

- **कितने देशों में पिया जाता है ऐसा दूध और कितना है अलग?**

नई दिल्ली। इन दिनों वेज मिल्क और नॉनवेज मिल्क पर जमकर बहस हो रही है. भारत दुनिया के सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करने वाले देशों में शामिल है. इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वहां केदूध के लिए भारत के बाजार खोल दिए जाएं, लेकिन भारत का साफ तौर पर कहना है कि जिन मवेशियों को ब्लड फूड या मांस आदि खिलाया जाता हो, उनका दूध यहां नहीं बेचा जा सकता है. क्योंकि भारत में दूध सिर्फ पीया नहीं जाता है, बल्कि उसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल किया जाता है.

भारत इसको लेकर नॉन निगोशिएबल नीति अपना रहा है और उसका कहना है कि अगर अमेरिका को अपने यहां का दूध भारत में बेचना है तो पहले यह कन्फर्म करना होगा कि वहां गायों ने मांस या मांस आधारित फूड न खाया हो. आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि क्या दूध भी नॉनवेज होता है और इस तरह का दूध किन देशों में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा यह दूध नॉर्मल मिल्क से कितना अलग होता है.

नॉनवेज क्यों माना जा रहा दूध

भारत में तो गाय, भैंस या बकरी जो कि दुधारू पशु हैं, वे शुद्ध शाकाहारी पशु होते हैं. वहीं भारत में तो गोवंश की पूजा भी की जाती है, इसलिए यहां गायों को नॉनवेज खिलाने का तो सवाल ही नहीं उठता है. इसीलिए यहां तो गाय-भैंस का दूध शुद्ध शाकाहारी होता है. वहीं अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं होता है, वहां पर मरे हुए जानवरों के मीट पाउडर, हड्डियों, फैट और खून से तैयार चारे को खिलाने वाली गायों से निकलने वाले दूध को शुद्ध शाकाहारी नहीं मानते हैं.

कौन से देश इस्तेमाल करते हैं नॉनवेज मिल्क

अब नॉनवेज मिल्क इस्तेमाल करने वाले देशों में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप, मेक्सिको, रूस, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राजील और पूरे यूरोप जैसे देश भी शामिल हैं. वहीं जापाम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी नॉनवेज मिल्क का बहुत इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन भारत में आज भी गायों को मुख्य रूप से हरा चारा, सूखा भूसा, मक्का, गेहूं के दाने और चोकर आदि खिलाया जाता है. लेकिन भारत में मांसाहारी चारे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.

टीम इंडिया पर टूटा मुसीबतों का पहाड़!

दो तेज गेंदबाज पहले थे चोटिल, बुमराह पर भी संशय

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का चौथा मैच (IND vs ENG 4th Test) 23 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाना है. उससे पहले ही टीम इंडिया को झटके पे झटके लगे जा रहे हैं. अर्शदीप सिंह पहले ही चोटिल हैं, वहीं अब आकाशदीप को भी फिटनेस संबंधी समस्याएं आने लगी हैं. आकाशदीप जिन्होंने बर्मिंघम टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट चटकाए थे, उन्हें पीठ में दर्द की समस्या है. ये मौजूदा सीरीज में पहली बार नहीं है जब आकाशदीप को फिटनेस संबंधी समस्या आई है, उन्हें लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी पीठ दर्द से जूझते देखा गया था.टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्शदीप और आकाशदीप के रिप्लेसमेंट के तौर पर अंशुल कंबोज को स्क्वाड में शामिल किया गया है. यह भी साफ कर दिया गया है कि जसप्रीत बुमराह मैनचेस्टर में खेलेंगे, जो 23 जुलाई से शुरू होना है. यह सीरीज शुरू होने से पहले ही साफ हो गया था कि बुमराह सीरीज में 3 मैच खेलेंगे, इसलिए बुमराह शायद ही सीरीज का आखिरी मैच खेलें.

बुमराह खेलेंगे, तो भी आएगी मुसीबत

इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अगले दो टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप एकसाथ नहीं खेलेंगे. इसलिए बुमराह मैनचेस्टर में खेलते हैं, तो द ओवल मैदान पर होने वाले अंतिम टेस्ट मैच में आकाशदीप, बुमराह की जगह लेंगे. चूंकि बुमराह और आकाशदीप एकसाथ नहीं खेलेंगे, इससे भारतीय पेस अटैक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है. इसलिए टीम इंडिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना लगभग तय है. आकाशदीप और अर्शदीप के चोटिल होने से भारतीय टीम को नेट प्रैक्टिस में भी परेशानी हुई. यहां तक कि गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल भी बॉलिंग करते दिखे. दूसरी ओर यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अंशुल कंबोज को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि उनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुभव नहीं है. आकाशदीप की बात करें तो उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टूर पर भी पीठ दर्द की समस्या हुई थी. फिलहाल तीन टेस्ट मैचों के बाद सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है, अगले दो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड और द ओवल मैदान पर खेले जाने हैं. भारत को सीरीज में बने रहने के लिए मैनचेस्टर टेस्ट हर हाल में जीतना होगा.

आखिरी 2 मैचों के लिए कंबोज टीम में शामिल

नई दिल्ली। तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 2 टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अर्शदीप सिंह उंगली में चोट के कारण चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से खेला जाएगा, जो टीम इंडिया के लिए 'करो या मरो' वाला है. तो क्या अंशुल जसप्रीत बुमराह की जगह चौथा टेस्ट खेलेंगे? बीसीसीआई ने बताया, "अर्शदीप सिंह के हाथ पर गहरा कट लग गया है, जिसके बाद टांके लगे. उन्हें पूरी तरह फिट होने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे, सिलेक्टर्स ने अंशुल कंबोज को टीम में शामिल करने का फैसला किया है."

चौथा टेस्ट खेलेंगे अंशुल कंबोज?

5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे, जिसमें से 2 वह खेल चुके हैं और अब 2 में से एक टेस्ट खेलेंगे. पहले तय किया गया था कि वह चौथा टेस्ट नहीं, पांचवा टेस्ट खेलेंगे हालांकि ये 'करो या मरो' वाला मैच है तो बुमराह अपना फैसला बदल भी सकते हैं. लेकिन अगर वह मैनचेस्टर में नहीं खेले तो संभव है कि अंशुल कंबोज को डेब्यू का मौका मिले. दरअसल प्रसिद्ध कृष्णा पहले 2 टेस्ट में काफी महंगे साबित हुए थे, इसलिए उनकी वापसी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है.अंशुल कंबोज पिछले महीने इंग्लैंड में ही थे, जहां इंडिया A के लिए खेलते हुए उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे. इन मैचों में उन्होंने कुल 5 विकेट लिए थे और 1 अर्धशतकीय पारी (51) समेत कुल 76 रन बनाए थे.

अंशुल कंबोज का करियर

अंशुल कंबोज ने किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया है. उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास मैचों में की 41 पारियों में 79 विकेट लिए हैं. इसमें वह 1 बार 10 विकेट भी ले चुके हैं, जबकि 2 बार 5 विकेट हॉल किया है. वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, उन्होंने 34 फर्स्ट क्लास पारियों में 16.20 की एवरेज से 486 रन बनाए हैं. इसके आलावा अंशुल कंबोज ने 25 लिस्ट ए मैचों में 40 विकेट और 30 टी20 मैचों में 34 विकेट लिए हैं।

टेस्ला की भारत में पहली कार लॉन्च मॉडल Y की कीमत 60 लाख से शुरू

नई दिल्ली। इलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के साथ लेवल-2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार को भारत में दो वैरिएंट- रियर व्हील ड्राइव (RWD) और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव (RWD) में पेश किया गया है। इसकी RWD वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपए है। वहीं लॉन्ग रेंज वैरिएंट की कीमत 68 लाख रुपए है। जबकि, ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है। कार की बुकिंग शुरू कर दी गई है। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से 22 हजार रुपए की टोकन मनी देकर इसे बुक कर सकते हैं। ईवी की डिलीवरी अक्टूबर से शुरू की जाएगी।

2 महीने पहले युद्ध जैसी थी स्थिति फिर क्यों रखा भारत-पाक मैच

नई दिल्ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की शुरुआत 18 जुलाई से हुई थी. इसमें भारत बनाम पाकिस्तान हाई-वोल्टेज मैच रविवार, 20 जुलाई को खेला जाना था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है. शिखर धवन, इरफान और यूसुफ पठान समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने इस मैच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, इसी कारण अब इस मैच को नहीं करवाया जाएगा. अब WCL ने स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि उन्हें भारत-पाकिस्तान मैच को क्यों रद्द करना पड़ा.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खस्ता हालत में जा पहुंचे थे. ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद WCL के आयोजकों ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच बुक करने का कारण बताते हुए कहा कि एक हालिया वॉलीबॉल मैच और आगामी हॉकी मैच के कारण उन्होंने ऐसा फैसला लिया. WCL ने X के माध्यम से बताया, "WCL में हमारी पूरी टीम क्रिकेट से अत्यंत प्रेम करती रही है. हम सिर्फ फैंस को अच्छे और यादगार पल देना चाहते हैं. हमने यह सुनने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-पाक मैच को बुक किया कि जल्द पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आने वाली है, वहीं हाल ही में हुए एक वॉलीबॉल मैच में दोनों देशों की टीम आमने-सामने आई थीं. हम सिर्फ फैंस को कुछ अच्छी यादें देना चाहते थे." वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के आयोजकों ने अनजाने में दिग्गजों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी भी मांगी. WCL ने पुष्टि करके बताया कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच को रद्द किया जा रहा है. आपको याद दिला दें कि WCL के पिछले सीजन में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था.

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर लगने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द ही मुहर लग सकती है. हाल ही में पांचवे दौर की वार्ता भी पूरी कर ली गई. इसमें ट्रे डील को अंतिम खाका पहनाना था. भारत के लिए यह डील अहम मानी जा रही है ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ से बचा जा सके और दूसरे एशियाई देशों से इस मामले में सबसे आगे रहा सके. यह वार्ता वॉशिंगटन में चार दिन (14 जुलाई-17 जुलाई) तक चली. बता दें कि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की डेडलाइन 1 अगस्त तय की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में कहा था कि भारत के साथ डील लगभग फाइनल है, लेकिन अगर इस बीच दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो भारत पर अमेरिका 26 परसेंट का टैरिफ लगा देगा.

ऑटोमोबाइल का अप्रैल-जून में बढ़ा 22 प्रतिशत एक्सपोर्ट

नई दिल्ली। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान 22 प्रतिशत का उछाल देखा गया है. इंडस्ट्री बॉडी सियाम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) का कहना है कि पैसेंजर व्हीकल के रिकॉर्ड निर्यात, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन खंड के शानदार परफॉर्मेंस से व्हीकल्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है. SIAM का कहना है कि जून तिमाही के दौरान सभी सेगमेंट्स में 14,57,461 यूनिट्स निर्यात किए गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान समान अवधि में 11,92,566 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए थे. यानी इसमें 22 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. पहली तिमाही के दौरान पैसेंजर व्हीकल्स में करीब 13 की उछाल देखने को मिला है और 2,04,330 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए. इनमें सबसे ज्यादा अब तक की शिपमेंट है।

क्या भारत से खेल सकती हैं ट्रांस वुमन अनाया बांगर?

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर ने पिछले वर्ष 'जेंडर चेंज' करवाया था. अब उन्हें अनाया बांगर के नाम से जाना जाता है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. दरअसल जेंडर बदलवाने से पहले अनाया पेशे से क्रिकेटर हुआ करती थीं और क्लब क्रिकेट में उन्हें काफी अनुभव रहा था. अब अगर अनाया दोबारा क्रिकेट खेलना चाहती हैं, तो क्या वो भारत की महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? 2024 महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में डेनियल मैकगेही का नाम खूब चर्चा में आया था. ऑस्ट्रेलिया में जन्मीं मैकगेही को वर्ल्ड कप के लिए कनाडाई स्क्वाड में चुना गया था. वो दुनिया की ऐसी पहली ट्रांस वुमन बनीं, जिन्होंने किसी देश की महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई थी. उन्होंने कनाडा के लिए 6 मैच खेले, लेकिन उसके बाद ICC ने अपने नियमों में बदलाव कर दिए थे. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने नवंबर 2023 में अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया था. नई पॉलिसी में बताया गया कि जो भी खिलाड़ी पुरुष यौवन के किसी भी रूप से गुजरा है, उसे महिला क्रिकेट मैचों में खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी. फिर चाहे उसने कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट क्यों ना करवाया हो. नई पॉलिसी में साफ किया गया कि कोई खिलाड़ी पुरुष से महिला से परिवर्तित हुआ है, उसे महिला क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी.

इन कारणों से अनाया बांगर को भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने और कोई मैच खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी. अनाया बांगर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखें तो वो अब भी अपने आपको क्रिकेटर बताती हैं. अपनी प्रोफाइल में उन्होंने क्रिकेटर के साथ-साथ खुद को मॉडल भी बताया है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

साप्ताहिक शहर सत्ता

भूपेश बघेल का साय सरकार पर बड़ा हमला

अगर मैं इतना प्रभावशाली हूं, तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए

रायपुर। राज्य में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्माई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित और बदले की कार्रवाई बताया है।

शुक्रवार, 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी सुबह 5:30 बजे भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापे के बाद हुई। गिरफ्तारी के बाद चैतन्य को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। रविवार को पार्टी ने रायपुर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में पुतला दहन और विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा: "ईडी का कहना है कि मैं बहुत प्रभावशाली हूं और इसलिए चैतन्य को गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर मैं वाकई इतना प्रभावशाली हूं, तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरफ्तारी अवैध रूप से और बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई है। बघेल का दावा है कि यह कार्रवाई अडानी समूह के दबाव में की गई है। "जिस दिन मैंने जंगल कटाई के खिलाफ स्थगन लाया, उसी दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, और उसी दिन ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है।"

कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई उद्योगपतियों के हित में की जा रही है। भूपेश बघेल और कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह गिरफ्तारी भूपेश बघेल की पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की मुहिम को दबाने के लिए की गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने इस मामले पर फोन और सोशल मीडिया के जरिए समर्थन जताया है। कांग्रेस ने 22 जुलाई को प्रदेशव्यापी चक्का जाम करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री का बयान: कांग्रेस की "बौखलाहट" पर तंज

राज्य में शराब घोटाले को लेकर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा पलटवार किया है। शनिवार को बिलासपुर में आयोजित रजक युवा गाडगे सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में साय ने विपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। विष्णुदेव साय ने कहा "लगातार हार से बौखलाए विपक्ष को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले और क्या न बोले। विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव—तीनों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसके कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई है।" साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सीबीआई को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सरकारों ने अडानी को कोल खदानों का आपरेटर बनाया: कश्यप

पिछली सरकार में भेजे सिफारिशी पत्र उजागर किए मंत्री ने

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप तथा भाजपा नेताओं ने रविवार की शाम भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कांफ्रेंस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला करते हुए उनकी सरकार में लिखे गए कई सिफारिशी पत्रों को सार्वजनिक किया है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार ने कोयला खदानों के आबंटन के लिए कई सिफारिशी पत्र लिखे थे और परमिशन दिलवाई थी।

प्रेस कांफ्रेंस में नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह, सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी मौजूद थे। मीडिया को संबोधित करते हुए वन मंत्री कश्यप ने कहा कि यह तथ्य है कि न केवल भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को आवंटित किया था, बल्कि उससे पहले भी कांग्रेसनीत केंद्र सरकार ने नियमविरुद्ध ढंग से छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक आवंटन की राह आसान की थी। साल 2010 में केन्द्र सरकार ने हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो-गो जोन घोषित किया गया, लेकिन उसी सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कुछ समय बाद ही इसे सबसे पहले गो-एरिया घोषित किया था।

मंत्री कश्यप ने कहा कि 23 जून 2011 को केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी को दो बड़ी खदानों गारे पेलमा सेक्टर-2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया गया।

कांग्रेस के घोटालों के अंतर्गत जेल में बंद कई लोगों को जमानत नहीं मिलीः चंद्राकर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अजय चन्द्राकर ने शनिवार को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है। वह अपने तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर काम करती है, कोई विधानसभा की कार्य सूची देखकर कार्य नहीं करती इसलिए ईडी की कार्यशैली पर कोई भी टिप्पणी वह (स्वयं श्री चन्द्राकर) नहीं कर सकते। श्री चन्द्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घपलों-घोटालों को लेकर गिरफ्तार किसी भी आरोपी को अभी तक जमानत नहीं मिली है और जिनको दो-तीन साल बाद जमानत मिली है, तो उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने को कहा गया है। अगर एजेंसियाँ गलत कर रही हैं तो न्यायालय तो गलत नहीं कर रहा है! उनको व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। कोई निर्दोष है तो उसे विचलित होने की जरूरत नहीं है।

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री चन्द्राकर ने बोरे-बासी घोटाले को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि कल उन्होंने पूछा था कि बोरे क्या है और बासी क्या है? छत्तीसगढ़ी खान-पान जो जानते हैं, वह समझते हैं कि दोनों अलग-अलग चीज है। बोरे अलग है और बासी अलग है। श्री चन्द्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में वह 1788 रुपए प्रति प्लेट मिला है तो यह कैसे मिला, क्या मिला, किस प्रक्रिया को अपनाया गया, इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में विधायकों की समिति जो विधानसभा में बनाई गई है, वह अब इस घोटाले की जाँच करेगी और तब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री चन्द्राकर ने प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों के मद्देनजर कहा कि यह इस सदी का नए तरीके का अपराध है। साइबर थाने खोलने, साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति, साइबर कमांडो बनने की बात करते हुए पुलिस इससे निपटने के लिए अपने आपको तैयार कर रही है, यह बात विधानसभा में गृह मंत्री ने कही है। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बात और कही है कि जनता में भी जागरूकता आनी चाहिए, और थोड़ा-सा भी संदेह होता है तो हेल्पलाइन नंबर, जिसे भारत सरकार ने दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस का भी नम्बर है, पर बताएँ।

धर्म परिवर्तन का आरोप : बजरंग दल ने चर्च के बाहर किया प्रदर्शन

भिलाई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में लगातार बवाल देखा जा रहा है। ताजा मामला भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र का है, जहां ढांचा भवन इलाके में एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जामुल क्षेत्र के सन मैरिज पैलेस के पास स्थित चर्च में रविवार को एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था।

इस सभा में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे। उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि वहां मौजूद लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चर्च में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला और बस में बैठाकर उन्हें उनके घरों के लिए रवाना कर दिया। इनमें से अधिकांश लोग कैंप और जामुल क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, इस सभा में साहू, कुर्मी, देवांगन और पटेल समाज के लोग भी शामिल थे। वहीं इस मामले को लेकर बजरंग दल की ओर से चर्च के पादरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसके आधार पर पुलिस ने पादरियों को हिरासत में लिए और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।

तीखे विरोध के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ माँ बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट चुनाव

डोंगरगढ़। रविवार को डोंगरगढ़ शहर पूरे दिन पुलिस की छावनी में तब्दील नजर आया। दरअसल, माँ बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के चुनाव को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आपत्ति दर्ज कराते हुए ट्रस्ट में 50% आरक्षण की मांग की थी। इसे देखते हुए प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर था और आंदोलन पर नजर रखते हुए डोंगरगढ़ के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। चुनाव की बात करें तो सुबह से ही मंदिर ट्रस्ट समिति के दोनों पैनल और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में जुटे रहे। इस दौरान तीन श्रेणियों में मतदान हुआ, साधारण श्रेणी में 1537 में से 1465, आजीवन श्रेणी में 917 में से 804 और संरक्षण श्रेणी में 522 में से 496 मतदाताओं ने मतदान किया।

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक 2025 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित

राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता, सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य की आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह विधेयक राज्य के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विधेयक के उद्देश्यों, प्रावधानों और इससे होने वाले लाभों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 दस्तावेज तैयार किया है, जिसके अंतर्गत राज्य को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य की वित्तीय दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह विशेष फंड स्थापित किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों से होने वाली आय में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 से 2024-25 के दौरान खनिज राजस्व में 30 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पूंजीगत व्यय में भी लगभग 43 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत तथा वर्ष 2023-24 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था को मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है, जिससे एक रुपये के निवेश से अर्थव्यवस्था को तात्कालिक रूप से 2.45 रूपए और दीर्घकाल में 3.14 रूपए का लाभ मिलता है। इसी दृष्टिकोण से यह फंड राज्य के पूंजीगत व्यय को सुदृढ़ करने सहायक होगा।

फंड के प्रमुख प्रावधान और लाभ

वित्त मंत्री ने बताया कि यह फंड खनिज संसाधनों से प्राप्त वार्षिक राजस्व का न्यूनतम 1 प्रतिशत और अधिकतम 5 प्रतिशत तक निवेश की व्यवस्था करेगा। फंड से प्राप्त लाभांश को पुनः फंड में निवेश किया जाएगा। इस फंड का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय के लिए ही किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में ही मूल राशि से आहरण किया जा सकेगा, वह भी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत तक। फंड की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत नियम बनाए जाएंगे, जिनमें फंड प्रबंधन, निवेश प्रक्रिया और अनुमति योग्य निवेश साधनों का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा।

राज्य के लिए ऐतिहासिक पहल

श्री ओपी चौधरी ने कहा कि ऐसा फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। मुख्य बजट 2025-26 में इस फंड के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज न्यास निधि का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज समेत कई जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

महिलाओं की आय बढ़ाने जिले में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती की शुरुआत

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन के मार्गदर्शन में बिहान योजना से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों (दीदियों) ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती की शुरुआत की है। इस कार्य में CSIR – केन्द्रीय औषधीय संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (Medicinal Plant Board) के विशेषज्ञों का तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहा है। योजना के प्रथम चरण में आरंग विकासखंड की तीन ग्राम पंचायत—बनचरोदा, छटेरा और चटोद में कुल 14 एकड़ पंचायत की सामुदायिक और व्यक्तिगत जमीन पर औषधीय पौधों जैसे बच, खस और ब्राह्मी का रोपण किया जा रहा है। इस नवाचारपूर्ण प्रयास के तहत औषधि बोर्ड ने महिला समूहों को निःशुल्क पौधों की आपूर्ति की है। दीदियों द्वारा तैयार कच्चे औषधीय माल को औषधि बोर्ड बाजार में बेचकर उसका मुनाफा सीधे महिला समूहों को देगा। इससे उनकी आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह योजना केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि एक हरित और स्वास्थ्यवर्धक भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम है।

कृषि यंत्रों से आसान हुई खेती किसानों के चेहरे खिले

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी योजनाओं एवं यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने से खेती-किसानी अब सुविधाजनक हो गई है। शासन की कृषि यांत्रिकीकरण सब-मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए वृहद पैमाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक ग्राम केसला के किसान श्री चोहलदास साहू को धान पैडी ट्रान्सप्लांटर मशीन के लिए 4 लाख 10 हजार रूपए का अनुदान मिला है। कृषक श्री साहू ने बताया कि मशीन की कुल कीमत 9 लाख रूपए है।

पैडी ट्रान्सप्लांटर से रोपा लगाने का काम काफी तेज, आसान और सटीक हो गया है। इससे श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है। इसकी मदद से एक दिन में 4 एकड़ भूमि में रोपा लगाया जा सकता है, जिससे खेती का काम पहले की तुलना में काफी तेज हो गया है। इसके उपयोग से फसल की बुवाई में पौधों की दूरी संतुलित रहती है, जिससे बीमारियां कम होती हैं और फसल का विकास बेहतर होता है। श्रमिकों पर निर्भरता भी घटी है और कृषि लागत में कमी आई है। मशीन से रोपा लगाने पर प्रति एकड़ 31 क्विंटल तक धान उत्पादन होता है। कृषक श्री साहू ने बताया कि पैडी ट्रान्सप्लांटर से धान की रोपाई के साथ-साथ अन्य किसानों की जमीन पर भी किराए से रोपा लगाने का कार्य कर रहे हैं।

बुढ़ापे का सहारा बनी महतारी वंदन योजना

- **श्रीमती सूरज बाई को मिली आत्मनिर्भर जीवन का संबल**

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्ध और जरूरतमंद महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। कोरबा जिले के विकासखंड कटघोरा के ग्राम धनरास निवासी 75 वर्षीय श्रीमती सूरज बाई अब पहले की तरह किसी से पैसे मांगने या उधार लेने को मजबूर नहीं हैं। राज्य सरकार से हर महीने 1,000 रुपये की सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचा रही है, जिससे वह अपने उपचार, दवाइयों, फल-सब्जी तथा अन्य आवश्यक जरूरतों को आसानी से पूरा कर रही हैं।

श्रीमती सूरज बाई बताती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ काम करना कठिन हो गया है, लेकिन महतारी वंदन योजना की राशि ने उनके जीवन को सहज और आत्मनिर्भर बना दिया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे शहर में कार्यरत हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए उन्हें पहले दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब सरकार की इस योजना ने उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है। श्रीमती सूरज बाई जैसी हजारों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली इस योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री

विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना वास्तव में प्रदेश की वृद्ध महिलाओं के लिए एक संजीवनी बनकर आई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि समाज की हर जरूरतमंद महिला को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए ताकि वे आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। महतारी वंदन योजना इसी दिशा में एक सशक्त कदम है, जो ग्रामीण अंचलों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही है।

'प्रोजेक्ट सुरक्षा' के तहत CPR का प्रशिक्षण

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जीवन रक्षक उपायों के प्रति जागरूकता और तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "प्रोजेक्ट सुरक्षा" के अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में में आज 'प्रोजेक्ट सुरक्षा' के अंतर्गत पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को प्राथमिक उपचार और CPR का जीवनरक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वी.आई.पी. सुरक्षा वाहिनी, माना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे PSO के लिए 4वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना रायपुर में किया गया।

चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र हित में नए नियम बनाए गए

चिकित्सा प्रवेश नियमों में व्यापक सुधार

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और चिकित्सकों की नई पीढ़ी के लिए सुलभ रास्ता तैयार करने को लेकर सचेत है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र हित में नए नियम बनाए गए हैं,जो चिकित्सा स्नातक छात्रों के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह नियम प्रवेश वर्ष 2025 हेतु हैं। इसके अनुसार चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. एवं बी.पी.टी.) पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग के लिए शासन द्वारा नवीन नियम संशोधन किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष से काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को अधिक सुविधा एवं पारदर्शिता मिलेगी।

प्राथमिकता में संशोधन

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रबंधन कोटा एवं एनआरआई कोटा में आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) की रिक्त सीटों के आवंटन में छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थियों को

प्राथमिकता दी जाएगी।

बॉन्ड सेवा अवधि में छूट

पूर्व निर्धारित 2 वर्षों के स्थान पर अब न्यूनतम 1 वर्ष की बॉन्ड सेवा अवधि अनिवार्य की गई है।

काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णत ऑनलाइन

समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। सीट आवंटन एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी।

ओबीसी श्रेणी हेतु आय प्रमाण पत्र में सरलता

ओबीसी वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण-पत्र संबंधित मापदंडों को सरल किया गया है।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी की रिक्त सीटें अब सामान्य वर्ग को

यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें अब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा।

प्रत्येक चरण में पंजीयन की सुविधा

काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया दिनांक 30 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। यह निर्णय राज्य के चिकित्सा विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

माँ सिर्फ किरदार नहीं भावना है

छत्तीसगढ़ी फिल्मों में माँ की भूमिका को जीवंत करती ये पांच अभिनेत्रियां

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

शहरसत्ता/रायपुर। जिस तरह हिंदी सिनेमा में निरूपा रॉय, रीमा लागू और फरीदा जलाल ने 'मां' के किरदार को अमर कर दिया, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा में भी कुछ ऐसी अदाकारा हैं, जिन्होंने परदे पर 'मां' को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि जिया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की लोकप्रिय और चर्चित फ़िल्मी माएं अंजलि चौहान, संगीता निषाद, उषा विश्वकर्मा, अनुराधा दुबे और उपासना वैष्णव ये वो नाम हैं जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपने अभिनय से कहानी को आधार देती हैं। इनका कहना है "मां के किरदार को निभाना अभिनय नहीं, एक साधना है।"

अभिनय की महारथी अंजली सिंह चौहान

से ज्यादा फिल्मों में दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी अंजली ने 'कारी', 'दइहान', 'मय दीया तैं मोर बाती' जैसी हिट फिल्मों में बहन, और बेटी के किरदारों को परदे पर जिया। उनका सपना 'बहादुर कलारिन' जैसा किरदार निभाना महिला सशक्तिकरण मिसाल हो। हर किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे कलाकार बड़ा बनाता है। सपनों का तो कोई अंत नहीं है और मुझे मां या सास का किरदार करने में बहुत अच्छा लगता है खुशी मिलती है क्योंकि आसान कुछ भी नहीं होता है।

चरित्र अभिनय की कठिन उपासना से निखरी उपासना

150 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी सना वैष्णव का अभिनय सफर छत्तीसगढ़ी सिनेमा विरासत है। गांव से निकलकर बड़े पर्दे तक ये सफर आसान नहीं था, लेकिन आज भी दर्शक 'मां' कहकर बुलाते हैं। कों की सराहना और स्ट्रीज से मिले प्यार, सम्मान और काम पर सना वैष्णव का कहना है... "अगर मैं लीजेंड हूं, तो काम मिलेगा ही।" कभी-कभी कोई एक रोल ऐसा भी आता है, जो दिल को छू जाता है। लगता है जैसे ये किरदार हमारा ही अक्स हो, हमारी ही अधूरी कही हुई बातें। क्योंकि फिल्मों में जो दिखता है, वो महज़ अभिनय नहीं होता उसमें कहीं न कहीं हमारी असल ज़िंदगी की परछाईं भी होती है।

अब उम्र नहीं सोच किरदार को बड़ा बनाती है - संगीता

से ज्यादा फिल्में कर चुकी संगीता निषाद खुद हिरोइन नहीं मानतीं, लेकिन उनकी दनशीलता और अभिनय सच्चाई उन्हें सबसे अलग ती है। "उम्र नहीं, सोच दार को बड़ा बनाती है।" उनका सपना भी 'बहादुर कलारिन' जैसे तिकारी नाट्य किरदार निभाना है। अपने अभिनय से भूमिका को जीवंत करने का अगर असल माद्दा है तो वह संगीता में दिखेगा। मैं तो कहती हूं कि आप काम इतना अच्छा कर लो कि आपको नई जनरेशन देखकर यह ना कहे कि यह भी हीरोइन रही होगी बल्कि हमें देखकर कहे हमने इन्हें देखकर काम सीखा है।

उषा कहती हैं किरदार बदलते हैं कलाकार नहीं

दिल से हीरोइन, परदे पर मां की भूमिका से न्याय करती आईं चरित्र अभिनेत्री उषा विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए जाना-पहचाना नाम है। 50 से अधिक फिल्मों में मां, सास, कॉलेज गर्ल से लेकर हर किरदार को जीवंत करने वाली ऊषा कहती हैं –"मैं हीरोइन थी, हूं और रहूंगी। किरदार बदलते हैं, कलाकार नहीं।" 28 साल की उम्र में मां बनीं, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी मां के रोल में उन्हें वो प्यार मिलता है जो हर कलाकार का सपना होता है।

मिसेस इंडिया से मां के किरदार तक – डॉ. अनुराधा दुबे

कथक में पीएच.डी., हिंदी साहित्य में एम.ए., 10 देशों में प्रस्तुति दे चुकीं डॉ. अनुराधा दुबे ने 'भूलन दी मेज' और 'बापू और स्त्री' जैसी फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। फ़िल्मी मां अनुराधा का मानना है कि पब्लिक का प्यार ही उनका अवॉर्ड है। अब वह निगेटिव किरदार भी पूरी शिदत्त से निभाने की चुनौती लेने तैयार हैं। हालांकि उनका सौम्य चेहरा, एक खतरनाक इरादा रखने वाली महिला से कितना मेल खायेगा यह वक्त बताएगा।

बिहार के बक्सर से मुंबई में बिना गॉड फॉदर के इंडस्ट्रीज में बन गए मिसाल

संतोष के चाल, चरित्र, चेहरा और अभिनय को नकारना नामुमकिन

शहर सत्ता/मुंबई/रायपुर। संतोष ओझा थिएटर से 'वीर सावरकर' फिल्म में लोकमान्य तिलक की भूमिका से संतोष ओझा का बेबाक फ़िल्मी सफर अब उरूज पर है। उनके अभिनय, फ़िल्मी अंदाज और चाल, चरित्र तथा चेहरे को नकारना अब इंडस्ट्रीज के लिए मुमकिन नहीं!" बिहार के बक्सर से निकलकर FTII और चंडीगढ़ इंडियन थिएटर से अभिनय की बारीकियां सीखने वाले संतोष ओझा का मानना है कि करियर में मिली पहली "ना" और "हां" दोनों ही उनके असली गुरु रहे हैं। उन्होंने 'लक्ष्मी बॉम्ब', 'मेड इन हेवन 2' और हालिया 'वीर सावरकर' में लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

संतोष मानते हैं कि सिर्फ लुक्स की पहचान कलाकार को संतुष्ट नहीं कर सकती। वे विविध और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में यकीन रखते हैं। सीमाएं तोड़ने की बात पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों को पार कर एक किरदार में खुद को ढाला।

बॉलीवुड में आउटसाइडर होने के दर्द पर वो साफ कहते हैं, "यहां सिर्फ टैलेंट नहीं, किस्मत और जुझारूपन भी चाहिए।" उन्होंने स्वीकार किया कि करियर बचाने के लिए कुछ नकारात्मक रोल भी निभाने पड़े जिन्हें करते वक्त आत्मग्लानि हुई, पर परफॉर्मेंस का संतोष मिला। सुपरस्टार बनने की चाह में उन्होंने गांव, मिट्टी और बचपन की बहुत-सी चीजें खो दीं, लेकिन आज भी सकारात्मक सोच के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। युवाओं को उनका संदेश है; मस्ती में मेहनत करो, भक्ति और शक्ति से जीवन को साधो।"

छत्तीसगढ़ का झुमका बोट क्लब निखरने को तैयार

कश्मीर की तर्ज पर तैरते हाउस बोट और शिकारा से सजेगा पर्यटन स्थल

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल झुमका जलाशय अब एक नए कलेवर में पर्यटकों का स्वागत करेगा। वर्षों से उपेक्षित पड़े झुमका बोट क्लब का पुनरुद्धार कार्य तेजी से जारी है। हैदराबाद से विशेष कारीगरों की टीम इस बोट क्लब को नए डिजाइन और सुविधाओं से सजाने का कार्य कर रही है। पर्यटन विभाग की योजना है कि सर्दियों के पीक सीजन तक यह पूरा स्थल पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। तैरते हुए हाउस बोट, शिकारा राइड, और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ यहां पर्यटकों को कश्मीर की डल झील जैसी अनुभूति कराने का प्रयास किया जा रहा है।

हाउस बोट की सुविधाएं

- 2 कमरे + हॉल की सुविधा वाले हाउस बोट
- 50 से अधिक पर्यटक एक साथ इस बोट का आनंद ले सकेंगे
- ऊपरी डेक पर किचन, जहां ब्रेकफास्ट और स्थानीय व्यंजन तैयार किए जाएंगे
- छत्तीसगढ़ी फूड के साथ "वॉटर डाइनिंग" का अनूठा अनुभव

पर्यटन के साथ रोजगार और राजस्व का साधन

- इस प्रोजेक्ट से सरकार को सालाना लगभग 18 लाख रुपये का अनुमानित लाभ
- हाउस बोट संचालन के लिए निजी एजेंसी को 5 लाख की अमानत और 1.5 लाख रुपये मासिक किराया देना होगा
- डीएमएफ फंड से 3 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना विकसित की जा रही है

झुमका बांध : पिकनिक का आदर्श स्थल

- झुमका जलाशय का निर्माण 1982 में अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुआ था
- यह बांध लगभग 1100 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करता है
- 17 गांवों के हजारों किसान इस जल स्रोत से लाभान्वित होते हैं
- प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और बोटिंग व फिशिंग जैसी गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है

फिश एक्वेरियम आकर्षण का केन्द्र

2016 में 35 लाख रुपये की लागत से यहाँ एक बड़ा फिश एक्वेरियम बनाया गया था। हालांकि देखरेख के अभाव में बोट क्लब और आसपास की संरचनाएं जर्जर हो गई थीं। अब पुनर्विकास के तहत इन सुविधाओं को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन से केवल 5 किमी दूर व कोरिया जिला मुख्यालय से 3 किमी की दूरी पर है झुमका जलाशय।

पैसा खुदा तो नहीं...फंस गए बिट्टू

पैसे ने सिर्फ अपना लिबास बदला, पहचान नहीं

कहानी एक होटल के बेसमेंट से शुरू होती है

जहां लाखों नहीं, करोड़ों की नकदी गिनी जाती थी

चैतन्य से मिले भूपेश बघेल, बेटी-बहू भी साथ रहीं

शिकंजा तब कसता है जब एक कारोबारी, जिसे पिता के करीबी माना जाता है। अपना बयान देता है। वह न सिर्फ पूरी रकम के प्रवाह की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी बताता है कि पैसों का एक हिस्सा एक राजनीतिक पार्टी के कोषाध्यक्ष को भी दिया गया। हैरानी की बात ये कि वह कोषाध्यक्ष पिछले दो साल से लापता है। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नकद अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित के जरिए उस युवा नेता तक पहुंचता था, जिसे अगली पीढ़ी का चेहरा माना जाता रहा है।

चैतन्य उर्फ़ बिट्टू पर ED ने क्यों कसा शिकंजा ?

- **करीबियों ने दिए सबूत,पेन-ड्राइव में लेन-देन का हिसाब मिला**
- **चैतन्य को बंसल-चावड़ा के जरिए मिला पैसा मिलने के सबूत**
- **शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप**
- **ED ने पप्पू बंसल और दीपेन चावड़ा से पूछताछ, समीक्षा के बाद गिरफ़्तारी**

शहर सत्ता/रायपुर। शराब कारोबार से जुड़ा कथित 3200 करोड़ रुपये का घोटाला अब अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता, सिंडिकेट और संतान- तीनों एक ही मंच पर हैं, लेकिन किरदारों की चुप्पी सबसे ज़्यादा बोल रही है। आरोप है कि बर्थ-डे बॉय को शराब सिंडिकेट से 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक कैश मैनेजमेंट के लिए मिले। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले में अब नजरें एक युवा चेहरे पर हैं। करोड़ों के नकद लेन-देन, निवेश, और सियासी कनेक्शन ने मामले को और पेचीदा बना दिया है।

ED के अफसरों को कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों का हिसाब-किताब मिला था। इसके साथ ही साक्ष्य मिले कि चैतन्य बघेल को पप्पू बंसल, दीपेन चावड़ा के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया। ED के वकील ने न्यायालय में ये बातें कही है। ये पैसा हवाला कारोबारी की मदद से चैतन्य बघेल ने अलग-अलग राज्यों में इन्वेस्ट करवाया। ED के अफसरों को चैतन्य के खिलाफ सबूत 10 मार्च को मारी गई रेड के अलावा 15 जुलाई को होटल कारोबारी के यहां मारी गई रेड से मिला है।

ED बढ़ा सकती है बिट्टू की रिमांड

ED ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक ED की 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। जानकारी में मुताबिक ED के पास साक्ष्य और कारण दोनों है। संभावना जताई जा रही है कि अगर 5 दिन की रिमांड में चैतन्य से कोई काम की बात नहीं उगलवा पाए तो ED रिमांड बढ़ने की मांग करेगी।

CM पुत्र के लिए 22 जुलाई से चक्काजाम

प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिलों, प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों में 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्काजाम कर अडाणी के लूट के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस प्रदेशभर में नाकेबंदी करेगी।

बिट्टू के बचाव में उतरी पूरी पार्टी, नेता बोले

भूपेश बघेल ने कहा कि पप्पू बंसल खुलेआम ED दफ्तर आ रहा है, EOW ऑफिस आ रहा है। उसके बयान पर मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया। न हमें नोटिस मिला और न ही दफ्तर बुलाया। ED के अफसर आए और गिरफ्तार कर लेकर गए। अडाणी के खिलाफ आवाज उठाने पर ये कार्रवाई हुई है।

दीपक बैज ने कहा कि अगर ED, CBI, EOW जैसी कोई और एजेंसी हो, तो उन्हें भी कार्रवाई के लिए आना चाहिए। आज भूपेश बघेल के घर पर कार्रवाई हुई है। हमारे एक नेता कवासी लखमा जेल में हैं। देवेंद्र यादव जेल में सजा काटकर आए हैं।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा- पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा, दिल जलाना होगा। बच्चे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है। सरकार एजेंसियों का उपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रही है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये अडाणी की सरकार है।

बेटे चैतन्य से मिलने ईडी ऑफिस जाते भूपेश, बेटी और बहु

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस बीच भूपेश बघेल बेटे चैतन्य से मिलने ED ऑफिस पहुंचे। बघेल के साथ उनकी बेटी और बहू भी मौजूद रही। भूपेश बघेल ने बताया कि बेटे से आधे घंटे मुलाकात हुई। 18 जुलाई को शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। 22 जुलाई तक ED ने चैतन्य को रिमांड पर लिया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के ED ऑफिस के एक कमरे में चैतन्य को बंद कर रखा गया है। जहां अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

क्या ऐसे हुआ निवेश का खेल ?

जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने इस अवैध आय को वैध दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स, संपत्तियों और कथित लोन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। कुछ संस्थानों को लोन दिखाया गया, लेकिन बदले में उन संस्थानों ने उसी प्रोजेक्ट में निवेश किया यानी पैसे ने सिर्फ अपना लिबास बदला, पहचान नहीं। अब ये घोटाला एक और अहम सवाल की तरफ बढ़ रहा है, जिस व्यक्ति के बयान पर गिरफ्तारी हुई, वही व्यक्ति आज़ाद क्यों घूम रहा है? शिकंजा तब कसता है जब एक कारोबारी, जिसे पिता का करीबी माना जाता है। अपना बयान देता है। वह न सिर्फ पूरी रकम के प्रवाह की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी बताता है कि पैसों का एक हिस्सा एक राजनीतिक पार्टी के कोषाध्यक्ष को भी दिया गया।

शिक्षा, व्यवसाय, सियासी कयास और आरोप

1. चैतन्य ने अपनी शुरुआती शिक्षा रायपुर के महर्षि विद्या मंदिर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भिलाई के शंकराचार्य विश्वविद्यालय से बीकॉम और भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए किया।

2. चैतन्य रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रिय हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्होंने अच्छी पहचान बनाई। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में उनकी फर्म ने अब तक 2 रिहायशी टाउनशिप विट्ठलपुरम और विट्ठलग्रीन्स बनाई है।

3. चैतन्य का कांग्रेस से जुड़ाव तो है, पर उन्होंने अब तक संगठन में कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं संभाली है। चैतन्य की राजनीति में एंट्री बघेल सरकार के समय प्रस्तावित था, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक खींचतान के चलते यह योजना अमल में नहीं आ सकी।

4. क़ानूनी मामलों में उनका नाम पूर्व में भी जांच के दायरे में आया, हालांकि अब तक किसी भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई 2024 में, खूबचंद बघेल पीजी कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए हमले की जांच के दौरान भी चैतन्य बघेल से पूछताछ की गई।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।